



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012026-269551
CG-DL-E-23012026-269551

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57]
No. 57]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2026/माघ 3, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2026/MAGHA 3, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 58(अ).—प्रस्तावित मसौदा नियम, जिन्हें (i) केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) की धारा 7 (2) 18 (2), 18 (3), 18 (6), 20 (5), 24 (2), 26 (2), 48 (2), 54 (2) 72 के साथ पठित धारा 76 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; और (ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से धारा 78 (2) के तहत धारा 1(3)(क)(iii), 11(2), 36, 38(1), 38(3), 39, 40(1), 40(2), 42(1), 44(1), 49, 67, 68 के साथ पठित धारा 78 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम को लागू किए जाने की तारीख को अथवा उसके बाद बनाने का प्रस्ताव करती है, यथा अपेक्षित, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर 22 फरवरी, 2026 के बाद विचार किया जाएगा।

इन मसौदा नियमों के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री नवीन कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 547, 5वीं मंजिल, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किया जा सकता है या ईमेल (uspd-psw@gov.in और sopd1-psw@gov.in) पर 22 फरवरी, 2026 तक या उससे पहले भेजा जा सकता है;

उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों को, इन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक नहीं माना जाएगा और इन्हें वैश्वासिक हैसियत में रखा जाएगा, ताकि हितधारक अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रदान कर सकें और केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अंतिम रूप देने से पहले इन पर समुचित विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

अध्याय I - प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता।

1. इन नियमों को भारतीय पत्तन नियम, 2026 कहा जाए।
2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
3. अध्याय I उन सभी पत्तनों पर लागू होगा जिन पर अधिनियम लागू होता है, जबकि इन नियमों के तहत अन्य अध्याय पत्तनों पर इस रीति से लागू होंगे:
 - क. महापत्तनों पर, इसके तहत बनाए गए सभी नियम;
 - ख. धारा 78(2) अर्थात् नियम 12 से 46, नियम 55, नियम 57 से 66 और धारा 76(2) के तहत बनाए गए नियम अर्थात् नियम 67.

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- क. “अधिनियम” से भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का 27) अभिप्रेत है;
- ख. “अग्रिम अपशिष्ट सूचना” या “एडब्ल्यूएन” से आगमन-पूर्व घोषणा अभिप्रेत है जिसमें इन नियमों के अनुसार, अधिनियम की धारा 39 के तहत दी गई जलयान पर और पत्तन पर प्रवाहित किए जाने के लिए अपशिष्ट संबंधी सूचना निहित हो।
- ग. "अभिकर्ता" से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 3(3) के तहत यथापरिभाषित अभिकर्ता अभिप्रेत है;
- घ. “आगमन रिपोर्ट” से अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत तथा इन नियमों के अनुसार जलयान के स्वामी, एजेंट या कप्तान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना अभिप्रेत है;
- ड. “लेखापरीक्षा प्राधिकारी” से वह प्राधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति, निकाय या एजेंसी अभिप्रेत है जिसे प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- च. “सुधारात्मक कार्रवाई योजना” से इन नियमों के नियम 33 के अंतर्गत विनिर्धारित योजना अभिप्रेत है, जो लेखापरीक्षा अवलोकनों, कमियों की प्रतिक्रिया में तैयार की

जाती है और जिसमें लेखापरीक्षा के दायरे के अनुसार पहचाने गए सुधारों के लिए रास्ता निहित होता है;

- छ. “नामोदिष्ट घटना रिपोर्टिंग अधिकारी” से पत्तन पर तैनात उप संरक्षक या समकक्षरैंक का अधिकारी अभिप्रेत है;
- ज. “निर्दिष्ट प्रणाली” से समुद्री एकल खिड़की या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अभिप्रेत है;
- झ. “व्यय” से उन उचित लागतों, शुल्कों और व्यय अभिप्रेत है, जिनमें अधिनियम की धारा 26(2) के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
 - i. मरम्मत या प्रतिस्थापन लागत,
 - ii. अस्थायी कार्य और आपातकालीन उपाय,
 - iii. पेशेवर और सर्वेक्षण शुल्क, और
 - iv. इन नियमों में दी गई अन्य संबंधित लागतें;

ज. “स्वास्थ्य अधिकारी” से अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

ट. “घटना” से अधिनियम की धारा 67 में संदेखित कोई घटना अभिप्रेत है;

ठ. “समुद्रवर्ती एकल खिड़की” से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है जो अन्य बातों के साथ-साथ कन्वेंशन ऑन फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रैफिक, 1965 के अनुसार पत्तन और पोत रिपोर्टिंग औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए मानकीकृत सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है;

ड. “ऐसे पत्तन की ओर जाने वाली नौगम्य नदी या नहरें” से किसी भी नदी, मुहाने, बैकवाटर, क्रीक, नहर, फेयरवे, चैनल या अन्य जलमार्ग अभिप्रेत है जो-

- i. पत्तन से आने-जाने वाले जलयानों द्वारा नियमित रूप से उपयोग में लाया जाता है, या उपयोग किए जाने का मंशा है; और
- ii. धारा 11(1) के अंतर्गत यथाअधिसूचित पत्तन सीमाओं के बाहर, या आंशिक रूप से बाहर स्थित है;

ढ. “राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना” से अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अभिप्रेत है।

ण. “अवरोध का स्वामी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास सरकार द्वारा जारी किया गया संबंधित परमिट, अनुदान, लाइसेंस या अन्य वैध लिखत है जिसके तहत अवरोध स्थापित या अनुरक्षित किया जाता है, और इसमें कोई भी रियायतग्राही, पटेदार या संचालक शामिल है जो अनुबंध या कानून के तहत ऐसे अवरोध के अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है;

“प्रदूषण घटना” से किसी पोत, पत्तन सुविधा या पत्तन सीमा के भीतर होने वाले संचालन से उत्पन्न होने वाली कोई भी घटना, परिस्थिति या स्थिति अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषण होता है या होने की संभावना होती है।

- i. तेल, तैलीय मिश्रण, तैलीय अवशेष का रिसाव, निकास, स्राव या फैलना;
- ii. हानिकारक तरल पदार्थों का रिसाव या रिसाव का खतरा;
- iii. एमएआरपीओएल के अंतर्गत हानिकारक पदार्थों का रिसाव या रिसाव का खतरा;
- iv. समुद्री पर्यावरण के लिए हानिकारक सीवेज, कूड़ा, प्लास्टिक, रसायन या अपशिष्ट की निकासी।

- v. कोई भी ऐसी स्थिति जो निम्नलिखित के लिए जोखिम पैदा करती हो:
- क. तटीय आबादी और तटीय जल के प्रयोक्ताओं का स्वास्थ्य;
 - ख. मत्स्य पालन और अन्य जीवित समुद्री संसाधन;
 - ग. तटीय और पत्तन संस्थापनाएं, सुविधाएं और सेवाएं;
 - घ. तटीय क्षेत्र के पर्यटन स्थल, सुविधाएं और अन्य आर्थिक हित; या
 - ड़. समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण
- vi. जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को खतरा;
- त “पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति एवं प्रबंधन योजना” या “योजना” से अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत तैयार और कार्यान्वित की गई योजना अभिप्रेत है;
- थ “प्राप्ति” से अधिनियम की धारा 48 के अनुसार शुल्क या अन्य प्रभारों के भुगतान के प्रमाण के रूप में जारी की गई औपचारिक अभिस्वीकृति अभिप्रेत है;
- द “तटीय कल्याण सुविधाएं और सेवाएं” से समुद्री श्रम सम्मेलन, 2006 के विनियम 4.4 के अंतर्गत परिकल्पित सुविधाओं और सेवाओं अभिप्रेत है, जिनका विवरण नौवहन महानिदेशालय के समय-समय पर अद्यतन किए गए कल्याण दिशानिर्देशों में दिया गया है;
- ध “अपशिष्ट वितरण पावती” या “डब्ल्यूडीआर” से किसी पत्तन द्वारा धारा 40(2) के अनुसार किसी रिसेप्शन सुविधा द्वारा पोत से अपशिष्ट की प्राप्ति की पुष्टि करने वाली पावती अभिप्रेत है।

अध्याय II – प्रशासन

क. धारा 7(2) के अंतर्गत वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें

3. नियुक्ति

1. परिषद में सामान्यतः ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया हो या प्रतिनियुक्त किया गया हो।
2. उप-नियम (2) के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें लागू मूल कैडर संवर्ग नियमों या केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किए गए संबंधित ग्रेडों को देय भत्ते भी लागू होंगे।

ख. धारा 18(2) के तहत नियुक्त किए जाने वाले पत्तन के अन्य अधिकारी और धारा 18(3) के तहत उनकी सेवा के नियम एवं शर्तें।

4. पत्तन पर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

1. प्रत्येक पत्तन, संरक्षक और हार्बर मास्टर के अतिरिक्त, उप-नियम (2) के अंतर्गत दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है।
2. उप-नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी समुद्री संचालन, प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, सुरक्षा और अधिनियम के तहत अन्य कार्यों का निर्वहन करेंगे।

बशर्ते कि एक या एक से अधिक अधिकारियों को ऐसे सभी या किसी भी कार्य या उसके भागों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

3. पत्तन अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति पत्तन के भर्ती नियमों के अनुसार होगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

5. पत्तन अधिकारियों का वेतन एवं भत्ते

इस नियम के अंतर्गत पत्तन अधिकारियों का वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

6. पत्तन अधिकारियों की सेवा शर्तें

पत्तन अधिकारियों की सेवा की अन्य शर्तें, जैसे अवकाश, कार्यकाल, परिवीक्षा अवधि, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता, कार्य घंटे, पदोन्नति, वरिष्ठता, आचरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही पत्तन के सेवा विनियमों के अनुसार होंगी, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

7. अन्य अधिकारियों के वर्गीकरण, नियुक्ति और पात्रता से संबंधित नियमों को शिथिल करने का अधिकार।

केंद्र सरकार लिखित रूप में दर्ज कारणों के आधार पर अधिकारियों के किसी वर्ग या श्रेणी के लिए इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

ग. संरक्षक द्वारा प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियाँ और वे व्यक्ति जिन्हें धारा 18(6) के अंतर्गत ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

8. संरक्षक की शक्तियों का प्रत्यायोजन

1. संरक्षक अधिनियम के अंतर्गत अपनी सभी या कोई भी शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य किसी भी अधिकारी को प्रत्योजित सकता है।

2. उपरोक्त उप-नियम (1) के अंतर्गत कोई भी प्राधिकार:

क. लिखित में होगा;

ख. प्रत्येक मामले में प्रत्यायोजन की प्रकृति और सीमा निर्दिष्ट होगी;

यदि संरक्षक व्यक्तियों का एक निकाय है, तो ऐसे निकाय के सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित किया जाएगा।

3. पत्तन की सुरक्षा या संरक्षा के हित में या किसी अन्य लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण से आवश्यक समझे जाने पर, संरक्षक को बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय शक्तियों के प्रत्यायोजन को रद्द करने, बदलने या निलंबित करने का अधिकार है।

घ. धारा 24(2) के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें एवं नियम

9. स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की विधि एवं सेवा शर्तें

1. प्रत्येक महापत्तन के लिए एक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

2. स्वास्थ्य अधिकारी के पास ऐसी अर्हताएं, अनुभव और सेवा की ऐसी अन्य शर्तें होनी चाहिए जो पत्तन स्वास्थ्य संगठन के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों।
3. स्वास्थ्य अधिकारी पत्तन पर स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम के तहत या केंद्र सरकार के निर्देशों द्वारा उसे सौंपे गए हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, 2005 का अनुपालन भी शामिल है।

ड. धारा 48(2) के अंतर्गत शुल्क या अन्य प्रभारों की प्राप्ति की विधि एवं तरीका

10. प्राप्ति जारी करने का दायित्व

अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत किसी भी शुल्क या अन्य प्रभार को वसूल करने के लिए अधिकृत प्रत्येक अधिकारी ऐसे भुगतान की स्वीकृति देते हुए प्राप्ति जारी करेगा।

11. प्राप्ति जारी करने का प्रपत्र और रीति

1. जारी की गई सभी प्राप्तियों में अनुसूची I में निर्दिष्ट विवरण होने चाहिए।
2. भुगतानकर्ता के लिखित अनुरोध पर जिसके साथ, पहचान और भुगतान प्रमाण हो, एक डुप्लिकेट प्राप्ति जारी की जा सकती है, जिसमें
3. सभी प्राप्तियां चूनतम सात वर्ष की अवधि के लिए रखी जाएंगी।
4. प्राधिकरण, प्राप्तियों को जारी करने के लिए प्रारूपों, डिजिटल टेम्पलेट्स या मानक संचालन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है।

अध्याय III- प्रदूषण

च. शर्तें जिनके अध्यधीन पत्तन धारा 36 के तहत रिसेप्शन सुविधाएं प्रदान करेगा

12. पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की स्थापना और उपयुक्तता

1. प्रत्येक पत्तन बिना किसी अनुचित देरी के, ऐसी पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं स्थापित, संचालित और अनुरक्षित करेगा जो पत्तन का सामान्य रूप से उपयोग करने वाले जलयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए-
 - क. पत्तन पर आने वाले जलयानों का आकार, प्रकार और यातायात प्रोफ़ाइल;
 - ख. सामान्य रूप से जलयान-जनित कचरे की प्रकृति, आवृत्ति और मात्रा; और
 - ग. पत्तन की प्रचालन विशेषताएं, जिनमें बर्थ विन्यास, टर्मिनल ले आउट और हैंडल किया गया कार्गो शामिल है।

2. पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं निम्नलिखित के अनुसार जलयान-जनित कचरे और अवशेषों को प्राप्त करने, अलग करने और संभालने जैसा कि लागू हो, में सक्षम होंगी:-
 - क. अनुबंध I (तेल, तैलीय मिश्रण, कीचड़ (sludge), बिल्ज वाटर, टैंक वॉशिंग और निकास गैस सफाई प्रणाली के अवशेष);
 - ख. अनुबंध II (हानिकारक तरल पदार्थ वाले अवशेष और मिश्रण);
 - ग. अनुबंध IV (सीवेज, शोधित और अशोधित ब्लैक वॉटर और ग्रे वॉटर सहित);
 - घ. अनुबंध V (श्रेणीवार अलग किया गया कचरा, जिसमें प्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट, प्रचालन अपशिष्ट, कार्गो अवशेष और अपशिष्ट शामिल है); और
 - ड. मार्पोल (MARPOL) कन्वेशन का अनुबंध VI (ओजोन-क्षयकारी पदार्थ, निकास गैस सफाई प्रणाली के अवशेष और अन्य वायु प्रदूषण नियंत्रण अवशेष)।
3. जहां लागू हो, पत्तन पक्ष के दायित्वों और जलयानों पर अनुमोदित बैलास्ट जल प्रबंधन प्रणालियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं बैलास्ट जल प्रबंधन कन्वेशन के अनुच्छेद 5 के अनुसार बैलास्ट जल और तलछट प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त होंगी।
4. उप-नियम (2) और (3) के प्रयोजनों के लिए, पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की उपयुक्तता का आकलन निम्नलिखित तकनीकी और प्रचालन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, अर्थात्:
 - क. क्षमता, जिसमें क्रमवर्ती पोर्ट ऑफ कॉल के बीच सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को हैंडल करने के लिए पर्याप्त भंडारण, उपचार या अंतरण क्षमता शामिल है;
 - ख. उपलब्धता, जिसमें प्रचालन के घंटे, प्रतिक्रिया समय और उचित सूचना पर कचरा प्राप्त करने की क्षमता शामिल है;
 - ग. पहुंच, जिसमें जलयान के प्रचालन में हस्तक्षेप किए बिना बर्ध, लंगर या टर्मिनलों पर सुरक्षित और व्यावहारिक पहुंच शामिल है;
 - घ. पृथक्करण और अनुकूलता, यह सुनिश्चित करना कि कचरे की विभिन्न श्रेणियों को अलग-अलग और डाउनस्ट्रीम उपचार या निपटान प्रणालियों के साथ संगत तरीके से हैंडल किया जाए;
 - ड. पर्यावरण और सुरक्षा नियंत्रण, जिसमें रिसाव रोकथाम, संरोधक, व्यावसायिक सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था शामिल है; और
 - च. जलयानों के साथ इंटरफ़ेस, जिसमें मानक जहाज प्रवाह व्यवस्था, होज़, कपलिंग और कनेक्शन पॉइंट के साथ अनुकूलता शामिल है।

5. पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की योजना और संचालन मांग-उत्तरदायी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा, जिसमें एडब्ल्यूएन के माध्यम से जानकारी, कचरा डिलीवरी संबंधी ऐतिहासिक डाटा, सुविधाओं की कथित अपर्याप्तता की कोई भी शिकायत या रिपोर्ट और जलयान प्रौद्योगिकी, ईंधन के प्रकार, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या अपशिष्ट धाराओं में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखा जाएगा।
6. उप-नियम (2) से (5) के पूर्वाग्रह के बिना, पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं, जहां तक व्यावहारिक हो, निम्नलिखित को प्राप्त करने में सक्षम होंगी:
 - क. वैकल्पिक ईंधन, तट बिजली प्रणाली और उत्सर्जन-उपशमन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से उत्पन्न कचरा; और
 - ख. तकनीकी विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में जलयान-जनित कचरे की कोई भी अतिरिक्त श्रेणियां जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं।
7. इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि पत्तन के लिए हर बर्थ पर कचरे के लिए समान सुविधाएं प्रदान करनी अपेक्षित है, बर्थें कि जलयान-जनित कचरे की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी अनुचित देरी और समुद्र में गैर-कानूनी प्रवाह के जोखिम के बिना, पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्था मौजूद हो।
8. पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं का डिजाइन, निर्माण और प्रचालन अनुसूची II में निर्दिष्ट तकनीकी और प्रचालन मानकों के अनुरूप होगा।

छ. धारा 38(1) के तहत पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रपत्र और रीति

13. **योजना का प्रपत्र और रीति**
 1. अधिनियम की धारा 38(1) के अनुसार बनाई गई पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और प्रबंधन योजना में, न्यूनतम रूप से, निम्नलिखित शामिल होंगे -
 - क. पत्तन या टर्मिनल पर सामान्य रूप से आने वाले जलयानों की आवश्यकता के आलोक में, अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन;
 - ख. अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं के प्रकार और क्षमता का विवरण;
 - ग. निर्धारित कचरे की प्राप्ति और संग्रह की प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण;
 - घ. शुल्क प्रणाली, यदि कोई हो, का विवरण;
 - ङ. पत्तन या टर्मिनल का उपयोग करने वाले व्यक्तियों, अपशिष्ट अनुबंधकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों के साथ चल रहे परामर्श की प्रक्रियाएं;

च. प्राप्त और प्रबंधित निर्दिष्ट कचरे का प्रकार और मात्रा

2. योजना में निम्नलिखित भी शामिल हो सकते हैं:
 - क. वितरण के लिए प्रासंगिक कानून और औपचारिकताओं का सारांश;
 - ख. अपशिष्ट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान;
 - ग. हार्बर या टर्मिनल में पूर्व-शोधन उपकरण और प्रक्रियाओं, यदि कोई हो, का विवरण;
 - घ. प्राप्त निर्दिष्ट कचरे की मात्रा रिकॉर्ड करने की विधियों का विवरण;

ड. इसका विवरण कि निर्दिष्ट कचरे का निपटान कैसे किया जाता है।
3. योजना में सभी हार्बर या टर्मिनल उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी भी शामिल हो सकती है:
 - क. निर्दिष्ट कचरे की उचित डिलीवरी के मौलिक महत्व का एक संक्षिप्त संदर्भ;
 - ख. प्रत्येक बर्थ पर लागू अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं का स्थान, जिसके साथ एक आरेख या मानचित्र हो;
 - ग. सामान्य रूप से निपटाए जाने वाले निर्दिष्ट कचरे की सूची;
 - घ. संपर्क बिंदुओं, प्रचालकों और दी जाने वाली सेवाओं की सूची;

ड. डिलीवरी की प्रक्रियाओं का विवरण;

च. शुल्क प्रणाली यदि कोई हो, का विवरण; और

छ. अपशिष्ट प्राप्ति सुविधाओं की कथित अपर्याप्तता की रिपोर्ट करने की प्रक्रियाएं।
4. पत्तन, एजेंटों सहित हितधारकों के साथ परामर्श करके योजना तैयार कर सकता है और प्राप्त किए जाने वाले संभावित कचरे की अधिकतम मात्रा पर विचार कर सकता है।
5. बोर्ड के अनुमोदन के बाद, योजना पहली बार में और महत्वपूर्ण परिवर्तनों के मामले में हर बार तीन महीनों के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
6. योजना, आईएमओ द्वारा अपनाए गए प्रासंगिक प्रारूपों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार और अनुरक्षित की जा सकती है।

14. योजना की समीक्षा और उपलब्धता

1. प्राधिकरण द्वारा हर दो साल में योजना की समीक्षा की जा सकती है।
2. योजना पत्तन उपयोगकर्ताओं को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से या प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रीति से उपलब्ध कराई जाएगी।

ज. धारा 38(3) के तहत पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और प्रबंधन योजना के बारे में जानकारी और ऐसी जानकारी के संप्रेषण की रीति

15. योजना के संबंध में जलयानों को संप्रेषित की जाने वाली जानकारी।

धारा 38 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक पत्तन यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी अनुमोदित पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और प्रबंधन योजना से निम्नलिखित न्यूनतम जानकारी उस पत्तन का सामान्य रूप से उपयोग करने वाले जलयानों को संप्रेषित की जाएः

क. नियम 13 के अनुसार पत्तन और योजना का विवरण।

ख. संपर्क और आपातकालीन जानकारी—

i. संबंधित संपर्क बिंदुओं की सूची;

ii. अपशिष्ट संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार पर्यावरण या स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क विवरण।

ग. शिकायत और फीडबैक तंत्र—

i. रिसेप्शन सुविधाओं की कथित अपर्याप्तता या अनुपलब्धता पर जलयानों द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, जहां लागू हो, आईएमओ रिपोर्टिंग प्रारूप और निर्दिष्ट संपर्क बिंदु के संदर्भ में;

ii. इसका उल्लेख कि शिकायत की प्राप्ति और उसका समाधान किस प्रकार होगा।

घ. पर्यावरण और सुरक्षा अपेक्षाएं—

i. कचरे की डिलीवरी के दौरान लागू कोई भी पत्तन-विशिष्ट पर्यावरणीय या व्यावसायिक सुरक्षा अपेक्षाएं, जिनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यातायात नियंत्रण और रिसाव रोकथाम उपाय शामिल हैं;

ii. अपशिष्ट स्थानांतरण प्रचालकों से संबंधित किसी भी स्थानीय निषेध या संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण।

16. योजना के संप्रेषण की रीति

नियम 15 में संदर्भित जानकारी अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पत्तन प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित रीति से संप्रेषित की जाएगी।

17. योजना में अद्यतन सूचना

नियम 15 के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी को पत्तन अपशिष्ट प्राप्ति और प्रबंधन योजना में भौतिक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए पत्तन प्राधिकरण द्वारा जहां तक व्यावहारिक हो अद्यतित रखा जा सकता है।

18. योजना में निहित जानकारी के संबंध में रिकॉर्ड का रखरखाव।

प्रत्येक पत्तन, कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित बनाए रखेगा:

क. विभिन्न समय पर संप्रेषित जानकारी दर्शने वाली प्रतियां;

ख. पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की पर्याप्तता, पहुंच या जानकारी की स्पष्टता के संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत के रिकॉर्ड, और उन पर की गई कार्रवाई।

ज. धारा 39 के तहत अग्रिम अपशिष्ट सूचना प्रस्तुत करने का प्रपत्र, रीति और समय

19. एडब्ल्यूएन प्रस्तुत करने का दायित्व.

1. पत्तन पर आगमन की मंशा वाला प्रत्येक जलयान कॉल के पत्तन को एक एडब्ल्यूएन प्रस्तुत करेगा।
2. एडब्ल्यूएन इसे नजरअंदाज करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा कि जलयान :
 - क. कचरा प्रवाहित करने का इरादा रखता है;
 - ख. उसके पास प्रवाह करने के लिए कोई कचरा नहीं है; या
 - ग. सभी कचरा जलयान पर रखना चाहता है।

20. एडब्ल्यूएन प्रस्तुत करने का समय।

1. एक एडब्ल्यूएन प्रस्तुत किया जाएगा:
 - क. जलयान के आगमन से कम से कम 24 घंटे पहले; या
 - ख. यदि यात्रा 24 घंटे से कम है, तो पिछले पत्तन से प्रस्थान का समय; या
 - ग. यदि कॉल का पत्तन 24 घंटे से कम समय पहले पता चलता है, तो जैसे ही जानकारी उपलब्ध हो।
2. प्रस्तुत जानकारी में किसी भी भौतिक परिवर्तन को यथाशीघ्र अद्यतित किया जा सकता है।

21. एडब्ल्यूएन का प्रपत्र

एडब्ल्यूएन इन नियमों के तहत निर्दिष्ट फॉर्म एडब्ल्यूएन-1 में प्रदान किया जाएगा।

22. एडब्ल्यूएन प्रस्तुत करने की रीति

एडब्ल्यूएन अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से पत्तन प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट रीति से प्रस्तुत किया जाएगा।

23. एडब्ल्यूएन का रिकॉर्ड रखना

1. पत्तन, प्रशासनिक और लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए एडब्ल्यूएन के रिकॉर्ड ऐसे तरीके से बनाए रखेगा जैसा वह निर्धारित करे।
2. एडब्ल्यूएन किसी भी हितधारक को उस रीति से उपलब्ध कराए जाएंगे जैसा कि पत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- ट. धारा 40(1) के तहत जलयान-जनित कचरे के वितरण की शर्तें

24. अपशिष्ट सौंपने का दायित्व।

1. जब तक उप-नियम (2) के तहत छूट न दी गई हो, पत्तन पर आने वाले जलयान का मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि मार्पेल (एमएआरपीओएल) कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार, समुद्र में कानूनी रूप से प्रवाह नहीं किए जा सकने वाले सभी जलयान-जनित कचरे को जलयान के पत्तन से प्रस्थान करने से पहले एक उपयुक्त पत्तन रिसेप्शन सुविधा को सौंपे जाएंगे।
2. एक पत्तन किसी जलयान को उप-नियम (1) में संदर्भित दायित्व से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकता है, जहां मास्टर संरक्षक या ऐसे नियुक्त अधिकृत व्यक्ति की संतुष्टि के लिए अनुसूची III में निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार प्रदर्शित करता है कि ऐसी शर्तें पूरी की गई हैं, और जहां ऐसी संतुष्टि विधिवत लिखित रूप में दर्ज की गई हैं।
- क. जलयान के पास बोर्ड पर शेष और अगले कॉल के पत्तन तक उत्पन्न होने वाले सभी जलयान-जनित कचरे के लिए पर्याप्त समर्पित और अलग झंडारण क्षमता है, ताकि मार्पेल (एमओआरपीओएल) कन्वेंशन के उल्लंघन में समुद्र में बिना किसी प्रवाह के यात्रा जारी रखी जा सके; और
- ख. जलयान-जनित कचरे की संबंधित श्रेणियों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त पत्तन रिसेप्शन सुविधाएं कॉल के अगले पत्तन पर, आईएमओ ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य विश्वसनीय और सार्वजनिक रूप से सुलभ स्रोतों के माध्यम से प्रकाशित जानकारी को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध हैं।
3. उप-नियम (2) के तहत दी गई कोई भी छूट लिखित रूप में दर्ज की जाएगी और लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए पत्तन द्वारा निर्धारित तरीके से रखी जाएगी।

4. पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं के अस्थायी ओवरलोडिंग, खराबी या अनुपलब्धता की स्थितियों में, संरक्षक, जहां तक व्यावहारिक हो—
- उन जलयानों को प्राथमिकता देगा जो उनके प्रकार, कार्गो, ईंधन या कचरे की विशेषताओं को देखते हुए समुद्री प्रदूषण का ज्यादा जोखिम प्रदान करते हैं;
 - वैकल्पिक रिसेप्शन व्यवस्था करने के लिए आस-पास के पत्तनों और सक्षम अधिकारियों, जैसा उचित हो, अधिकृत अपशिष्ट रिसेप्शन प्रचालकों, और अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा; और
 - यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी देरी या वैकल्पिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप समुद्र में जलयान-जनित कचरे का गैर-कानूनी प्रवाह न हो।
- ठ. धारा 40(2) के तहत अपशिष्ट डिलीवरी की प्राप्ति (डब्ल्यूडीआर) जारी करने का प्रपत्र और रीति

25. डब्ल्यूडीआर जारी करने का दायित्व.

- प्रत्येक रिसेप्शन सुविधा जलयान से कचरा प्राप्त करने पर एक डब्ल्यूडीआर जारी करेगी।
- डब्ल्यूडीआर की एक प्रति निम्नलिखित को प्रदान की जाएगी:::

 - मास्टर,
 - जलयान के एजेंट, और
 - पत्तन/प्राधिकरण

26. डब्ल्यूडीआर का प्रपत्र

- डब्ल्यूडीआर को इस नियम के तहत निर्धारित विवरणों के अनुसार जारी किया जाएगा;
- फॉर्म में शामिल होंगे:
 - जलयान का विवरण, नाम और आईएमओ नंबर सहित;
 - मार्पेल कन्वेंशन (एमएआरपीओएल) के अनुबंध-वार संदर्भित सौंपी गई कचरा श्रेणियां;
 - अनुबंध I: तैलीय कचरा/स्लज/बिल्ज
 - अनुबंध II: हानिकारक तरल अवशेष
 - अनुबंध IV: सीवेज
 - अनुबंध V: कचरा श्रेणियां क-छ

v. अनुबंध VI: निकास गैस सफाई अवशेष

- ग. सौंपी गई कचरे की मात्रा, माप की इकाई सहित;
- घ. कचरा प्राप्त करने वाली पत्तन रिसेप्शन सुविधा का विवरण;
- ङ. सौंपने की तिथि और समय;
- च. कचरे की प्राप्ति की स्थिति, जिसमें पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति शामिल है;
- छ. कचरे की प्राप्ति और आगे प्रबंधन या स्थानांतरण की पुष्टि, जैसा भी लागू हो; और
- ज. पत्तन रिसेप्शन सुविधा और जलयान के मास्टर या अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण।

27. डब्ल्यूडीआर जारी करने का तरीका।

1. डब्ल्यूडीआर अधिमानत: इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप में जारी किया जा सकता है।
2. जलयानों से अपशिष्ट प्रवाह पूरा होने के एक घंटे के भीतर डब्ल्यूडीआर जारी किया जाएगा। यदि एक घंटे के भीतर रसीद जारी नहीं की जाती है, तो देरी और उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
3. डब्ल्यूडीआर में सभी मात्राएं मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त की जाएंगी, और दशमलव संकेतन का संगत उपयोग किया जाएगा।
4. डब्ल्यूडीआर अंग्रेजी में पूरा किया जाएगा, और सुविधा के लिए किसी भी अतिरिक्त भाषा में अनुवाद प्रदान किया जा सकता है; असंगति के मामले में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

28. कचरे की मल्टीपल या आंशिक डिलीवरी

जहां कचरा एक से अधिक बैच में डिलीवर किया जाता है, अलग-अलग डब्ल्यूडीआर जारी किए जा सकते हैं।

29. डब्ल्यूडीआर के संबंध में रिकॉर्ड रखने की अपेक्षाएं

रिसेप्शन सुविधा, सभी डब्ल्यूडीआर का डिजिटल या भौतिक रिकॉर्ड बनाए रखेगी और आवश्यकतानुसार किसी भी हितधारक के साथ साझा कर सकती है।

30. डब्ल्यूडीआर के संबंध में पोर्टल के साथ एकीकरण।

पत्तन या रिसेप्शन सुविधा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि डब्ल्यूडीआर के संबंध में अपलोड किए जाने वाले सभी आवश्यक डाटा क्षेत्र, अधिनियम की धारा 43 के अनुसार सटीक और समय पर पूरे किए गए हैं।

ड. धारा 42(1) के तहत पत्तनों के लेखापरीक्षा के अंतराल और रीति

31. लेखापरीक्षा के क्षेत्र

लेखापरीक्षा रिसेप्शन सुविधाओं की उपलब्धता और पर्याप्तता की जांच के उद्देश्य से किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की लेखापरीक्षा शामिल होगी, और इसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- क. मार्पोल (एमएआरपीओएल) कन्वेंशन के अनुबंध I, II, IV, V और VI के लिए पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की पर्याप्तता और प्रचालन स्थिति;
- ख. योजना का कार्यान्वयन और प्रभावशीलता;
- ग. जलयानों से प्राप्त कचरे के निपटान के लिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन;
- घ. बैलास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन के अनुसार पत्तन-पक्ष की सुविधाओं और दायित्वों पर लागू सीमा तक अनुपालन और प्रचालन तत्परता।

32. लेखापरीक्षा की आवृत्ति

1. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानकों और समुद्री प्रशासन महानिदेशक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पत्तन की हर दो साल कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।
2. ऐसी द्विवार्षिक लेखापरीक्षा समुद्री प्रशासन महानिदेशक के विधिवत अधिकृत लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

33. लेखापरीक्षा के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप और प्रलेखीकरण

1. लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - क. पत्तन के समग्र अनुपालन स्तर का संक्षिप्त सारांश;
 - ख. समयबद्ध सुधारात्मक कार्य योजना, जिम्मेदार पक्ष और पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथियां:
 - i. 90 दिनों से अधिक, और इसमें तकाल की जाने वाली कार्रवाई का विवरण हो;
 - ii. या ऐसी विस्तारित अवधि जैसा कि लेखापरीक्षा प्राधिकरण द्वारा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

34. लेखापरीक्षा के संबंध में डाटा प्रबंधन और गोपनीयता।

अधिनियम की धारा 42 के तहत आयोजित लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, पत्तन, ऐसी जानकारी और रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करके लेखापरीक्षा प्रक्रिया को सुगम बनाएगा, जो इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत बनाए रखना आवश्यक है, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं संबंधित रिकॉर्ड को कम से कम 7 वर्षों तक सुरक्षित रखेगा।

ढ. धारा 44(1) के तहत घटनाओं की रिपोर्टिंग की रीति

35. प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्ट करने का दायित्व

प्रत्येक पत्तन, पत्तन सीमा के भीतर किसी भी वास्तविक या संभावित प्रदूषण घटना की जानकारी होने के बाद यथाशीघ्र सरकार को रिपोर्ट करेगा।

36. प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्टिंग का समय

1. नियम 35 के तहत प्रत्येक रिपोर्ट के लिए:

- क. मास्टर अविलंब एक प्रारंभिक मौखिक रिपोर्ट और किसी भी स्थिति में पता चलने के 15 मिनट के भीतर रिपोर्ट करेगा।
- ख. पत्तन द्वारा घटना के 2 घंटे के भीतर, या यदि रोकथाम के उपाय चल रहे हैं तो व्यवहार्य रूप से यथाशीघ्र, प्रपत्र सीपीआईआर-1 में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- ग. पत्तन द्वारा, यदि कोई और जानकारी उपलब्ध होती है, 24 घंटे के भीतर, जो उन पूछताछों के अध्यधीन, जो पत्तन सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ कर सकता है, एक विस्तृत पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

37. प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्टिंग की रीति

1. नियम 36 के तहत प्रारंभिक मौखिक रिपोर्ट निम्नलिखित को दी जाएगी —

क.. निर्दिष्ट वीएचएफ चैनल पर वीटीएस /पत्तन नियंत्रण को; या

ख. आपातकालीन प्रदूषण हॉटलाइन पर निर्दिष्ट पत्तन अधिकारी को;

ग. तेल, तैलीय मिश्रण, तैलीय अवशेषों के प्रवाह, निकास, रिसाव या फैलाव के मामले में समुद्री प्रशासन संचार महानिदेशालय (डीजीसीओएम) को।

2. नियम 36 के तहत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी —

क. पत्तन समुदाय प्रणाली (पीसीएस) या मैरीटाइम सिंगल विंडो के माध्यम से; या

ख. पत्तन के ऑनलाइन प्रदूषण रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से; या

ग. निर्दिष्ट प्रदूषण रिपोर्टिंग पते पर ईमेल द्वारा।

3. यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा अनुपलब्ध है, तो सिस्टम बहाली के 3 घंटे के भीतर संरक्षक को एक हस्ताक्षरित भौतिक दी जानी चाहिए।

38. इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का उपयोग।

केंद्र सरकार, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के तहत प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार तंत्र निर्दिष्ट कर सकती है।

अध्याय IV- विविध

ग. धारा 1(3)(क)(iii) के तहत पत्तनों तक जाने वाली नौगम्य नदियों या चैनलों के किसी भी हिस्से की अधिसूचना का प्रपत्र और रीति

39. नौगम्य नदी की अधिसूचना के संबंध में उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत।

1. नियम 40 के तहत नौगम्य नदी या ऐसे पत्तन तक जाने वाले चैनलों को अधिसूचित करते समय, निम्नलिखित उद्देश्यों और सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाएगा, अर्थात्:
 - क. यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा, नौचालन, पर्यावरण संरक्षण और शुल्क एवं प्रभारों की वसूली के प्रयोजनों के लिए ऐसे पत्तनों तक जाने वाली नौगम्य नदियों या चैनलों पर अधिनियम के लागू किए जाने की स्थानिक सीमा स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित हो;
 - ख. पत्तन सीमाओं, पत्तन तक जाने वाले चैनलों और आसपास के नौगम्य जलमार्गों के बीच निरंतरता सुरक्षित करना, और अधिकारियों के बीच अधिकार क्षेत्र में अस्पष्टता या ओवरलैप से बचना.

40. पत्तनों तक जाने वाली नौगम्य नदियों या चैनलों की अधिसूचना का प्रपत्र प्रपत्र में फॉर्म I में निर्दिष्ट विवरण होंगे।

41. नौगम्य नदियों के संबंध में अधिसूचना के प्रकाशन का तरीका।

1. प्रत्येक अधिसूचना —

- क. सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी;
- ख. सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी;
- ग. पत्तन अधिसूचना को ऐसे अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

42. नौगम्य नदी की अधिसूचना के संबंध में निर्वचन

नियम 40 के तहत जारी अधिसूचना के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

त. धारा 11(2) के तहत एक नए पत्तन को अधिसूचित करने और पत्तन सीमाओं में बदलाव का मानदंड, प्रपत्र और रीति

43. नए पत्तन की घोषणा के लिए मानदंड

1. एक नया पत्तन तभी घोषित किया जाएगा जब प्रस्ताव निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो, अर्थात्:

- क. कार्यनीतिक और आर्थिक औचित्य: निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पत्तन क्षमता या विशिष्ट सुविधाओं की स्पष्ट आवश्यकता है;
 - i. अनुमानित कार्गो और यात्री मांग और आंतरिक क्षेत्र संपर्कता;
 - ii. राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना और उससे प्राप्त कोई भी क्षेत्रीय या सेक्टरल योजनाएं; और

- iii. लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, टर्नअराउंड समय कम करने और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करने की क्षमता;
 - iv. प्रस्ताव को वित्तीय व्यवहार्यता के प्रारंभिक मूल्यांकन द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें पूँजी और प्रचालन लागत अनुमान और संभावित वित्त पोषण स्रोत शामिल हैं।
2. गैर-दोहराव और पूरकता: प्रस्तावित नया पत्तन, मौजूदा पत्तनों के निकट क्षमता के अनावश्यक दोहराव का परिणाम नहीं होना चाहिए, और जहाँ एक क्षेत्र में कई पत्तन मौजूद हैं, प्रस्ताव में यह उल्लेख होगा कि नया पत्तन मौजूदा सुविधाओं की व्यवहार्यता को कैसे पूरक करेगा और भौतिक रूप से विकृत नहीं करेगा, सिवाय जहाँ व्यापक सार्वजनिक हित में उचित हो।
 3. सुरक्षा और रक्षा विचार: प्रस्तावित पत्तन का स्थान और वांछित संचालन, राष्ट्रीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और रक्षा विचारों के अनुरूप हैं, और प्रस्ताव में सक्षम सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों के विचार शामिल हैं।
 4. केंद्र सरकार लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, असाधारण मामलों में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट एक या अधिक मानदंडों में छूट दे सकती है जहाँ कार्यनीतिक, सुरक्षा या अन्य सार्वजनिक हित के विचार इसकी गारंटी देते हैं।
- 44. पत्तन सीमाओं में परिवर्तन के लिए मानदंड.**

पत्तन सीमाओं के परिवर्तन को अधिसूचित करने से पहले, सरकार सुनिश्चित करेगी:

- क. सामरिक और आर्थिक औचित्य;
- ख. सुरक्षा और रक्षा विचार;
- ग. नौगम्य सुरक्षा प्रभाव;
- घ. समुद्री ज़ोनिंग;
- ड. पर्यावरण संरक्षण; और
- च. कोई अन्य मानदंड जैसा कि सरकार निर्दिष्ट करे।

- 45. नए पत्तन की अधिसूचना और पत्तन सीमाओं में बदलाव की रीति**
नए पत्तन की घोषणा करने वाली प्रत्येक अधिसूचना और पत्तन सीमाओं को बदलने वाली प्रत्येक अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में क्रमशः फॉर्म II और फॉर्म III में निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

- 46. नए पत्तन और पत्तन सीमाओं के परिवर्तन की अधिसूचना का निर्वचन।**
जहाँ नए पत्तन की अधिसूचना या पत्तन सीमाओं के परिवर्तन के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, वहाँ केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

थ. धारा 20(5) के तहत अवरोध को हटाने या बदलने का तरीका और मुआवजे के निर्धारण के कारक

- 47. कानूनी अवरोध को हटाने या बदलने के संबंध में उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत.**

किसी भी अवरोध को हटाने या बदलने के लिए नियोजन और संचालन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- क. नौगम्य सुरक्षा सुनिश्चित करना;
- ख. पत्तन प्रचालन की रक्षा करना;
- ग. जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के जोखिम को कम करना;
- घ. नौचालन और पत्तन सुरक्षा की रक्षा की आवश्यकता के अध्यधीन, अवरोध के स्वामी के मौजूदा कानूनी अधिकारों का सम्मान करना।

48 कानूनी अवरोध लगाने वाले स्वामी के साथ परामर्श और नोटिस।

1. जहाँ अवरोध मौजूद है, संरक्षक ऐसे स्वामी को एक लिखित नोटिस जारी करेगा।
2. संरक्षक, जहाँ उचित हो और स्थिति की ताल्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, अवरोध लगाने वाले और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श बैठक या तकनीकी चर्चा बुला सकता है; या संबंधित प्राधिकरण या अन्य सक्षम निकाय के विचार मांग सकता है।

49 कानूनी अवरोध को हटाने या बदलने का तरीका।

संरक्षक, जहाँ तक व्यावहारिक हो, हटाने या बदलने की ऐसी रीति अपनाएगा:

- क. जिससे अवरोध के वैध स्वामी पर प्रभाव में कमी आती है;
- ख. जो जलयान यातायात और आवश्यक पत्तन सेवाओं में व्यवधान को कम करता हो;
- ग. जिसमें अतिरिक्त पर्यावरणीय प्रभावों से बचने या कम करने का प्रयास किया गया हो; और
- घ. जो भविष्य की विकास योजनाओं और पत्तन एवं जलमार्ग के निर्दिष्ट उपयोगों के अनुरूप हो।

50 कानूनी अवरोध के संबंध में आपातकालीन उपाय

1. जहाँ बाधा पर्यावरण, जीवन, नौचालन, पत्तन बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल कोई जोखिम पैदा होता है, संरक्षक लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ ऐसे तत्काल ऐसे उपाय कर सकता है जो आवश्यक हों।
2. संरक्षक ऐसी आपातकालीन कार्रवाई के बाद यथाशीघ्र अवरोध लगाने वाले (जहाँ पहचान योग्य हो) की गई कार्रवाइयों और उनके कारणों के बारे में सूचित करेगा, और उप-नियम (1) के अनुसार प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को निर्धारित करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा।

51. कानूनी अवरोध लगाने वाले को देय प्रतिपूर्ति के निर्धारण के कारक

उचित प्रतिपूर्ति का निर्धारण, हटाने या बदलने के समय बाधा की आयु, डिजाइन जीवन, संरचनात्मक स्थिति और शेष सेवा काल, वित्तीय निहितार्थ और मामले के ऐसे अन्य प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों जो लिखित में दर्ज किए जाएं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

52. कानूनी अवरोध के संबंध में प्रलेखीकरण

1. संरक्षक, अवरोध लगाने वाले से प्रतिपूर्ति का आकलन करने के लिए आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेज और डाटा यथाशीघ्र और किसी भी मामले में अविलंब प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।
2. संरक्षक प्रतिपूर्ति पर तर्कसंगत सिफारिश तक पहुँचने के लिए स्वतंत्र तकनीकी, वित्तीय या मूल्यांकन विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

- संरक्षक द्वारा धारा 26(2) के तहत भुगतान किए जाने वाले व्ययों के निर्धारण में विचार किए जाने वाले कारक

53. व्यय के निर्धारण हेतु उद्देश्य और मार्गदर्शक सिद्धांत

1. पत्तन या पत्तन सुविधाओं को हुई क्षति, विधंस या हानि के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति ऐसी संपत्ति या सुविधाओं को घटना से ठीक पहले की स्थिति में यथासंभव बहाल करने की पूरी लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि प्राधिकरण को कोई नुकसान न हो।
2. संरक्षक आनुपातिक आधार पर ऐसे व्यय अधिरोपित करेगा और इसे अन्यथा प्रभावित करने का उत्तरदायित्व धारा 26 की उपधारा (1) के तहत उत्तरदायी व्यक्ति का होगा।

54. हानि, विधंस या क्षति के आकलन के लिए निरीक्षण।

क्षति की प्रकृति, गंभीरता और तकनीकी जटिलता के आधार पर, संरक्षक ऐसी हानि या क्षति की प्रकृति और स्पष्ट सीमा की पहचान करने के लिए प्रारंभिक निरीक्षण या विस्तृत स्थिति सर्वेक्षण या इंजीनियरिंग मूल्यांकन, जैसा भी मामला हो, करने का निर्देश दे सकता है।

ध. धारा 49 के तहत पत्तन पर जलयान के आगमन की रिपोर्ट करने का प्रपत्र, रीति और समय

55. मैरीटाइम सिंगल विंडो के अनुसार जलयान आगमन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व
धारा 49 के तहत आगमन की रिपोर्ट करने का दायित्व मैरीटाइम सिंगल विंडो या केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार होगा।

न. धारा 54(2) के तहत व्यक्तियों के निकाय से संरक्षक की नियुक्ति का तरीका

56. जुर्माना लगाने के लिए व्यक्ति की नियुक्ति

धारा 54 की उप-धारा (2) के उद्देश्यों के लिए, बोर्ड ऐसे व्यक्तियों के निकाय में से सामान्य या विशेष संकल्प के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

प. धारा 67 के तहत घटनाओं की रिपोर्टिंग का तरीका

57. घटना की रिपोर्ट करने का दायरा और दायित्व

निर्दिष्ट घटना रिपोर्टिंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 67 के तहत किसी भी घटना का विवरण निम्नलिखित से अविलंब प्राप्त किया जाए —

- क. घटना में शामिल किसी भी जलयान स्वामी, एजेंट या मास्टर; और
- ख. घटना से प्रत्यक्ष प्रभावित या उसमें शामिल कोई भी टर्मिनल, सुविधा या पत्तन सेवा प्रदाता।

58. पत्तन द्वारा घटना की रिपोर्टिंग का समय और तरीका

धारा 67 के तहत एक लिखित रिपोर्ट यथासंभव शीघ्र और किसी भी स्थिति में घटना के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे प्रपत्र में, जैसा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डीजीसीओएम को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें वह समय भी शामिल है जब पत्तन तत्काल प्रतिक्रिया या सुरक्षा कार्यों में शामिल हुआ हो।

59. घटना की रिपोर्टिंग के संबंध में पंजीकरण और रिकॉर्ड-कीपिंग।

प्रत्येक पत्तन उपरोक्त नियम के तहत रिपोर्ट की गई सभी घटनाओं के साथ-साथ सभी रिपोर्टों और डीजीसीओएम से प्राप्त किसी भी पावती को दर्ज करते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक घटना रजिस्टर बनाए रखेगा।

V. धारा 68 के तहत तट आधारित कल्याणकारी सेवाओं के प्रावधान

60. सुविधा के लिए मानक।

धारा 68 के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनों के लिए पत्तनों को समुद्री प्रशासन के महानिदेशक द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश का उचित ध्यान रखना चाहिए।

61. तट-आधारित कल्याण सुविधा में भेदभाव का न होना।

1. नाविकों को सभी तट-आधारित कल्याणकारी सुविधाएं और सेवाएं लिंग, राष्ट्रीयता, जाति, रंग, लिंग या लागू कानून या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री श्रम मानकों के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना उपलब्ध कराई जाएंगी।
2. पत्तन, महिला नाविकों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे।

62. पत्तन-आधारित कल्याण सुविधा में पहुंच और सुविधा।

पत्तन सुरक्षा आवश्यकताओं, टर्मिनल स्थान और परिचालन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तट-आधारित कल्याणकारी सेवाओं तक उचित पहुंच को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करेंगे।

63. रिमोट और उच्च-सुरक्षा टर्मिनल।

जहां टर्मिनल दूर हैं या उन पर उच्च सुरक्षात्मक प्रतिबंधों के अध्यधीन हैं, वहां पत्तन नाविकों की कल्याण संबंधी सेवाओं की सार्थक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था सहित उचित उपाय विनिर्दिष्ट करेगा।

64. तट-आधारित कल्याण सुविधा में सेवाएं।

पत्तन के आकार और यातायात के आधार पर लचीलेपन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 के विनियम 4.4 के संबंध में तट-आधारित कल्याण सुविधाओं और सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- क. इंटरनेट कनेक्टिविटी;
- ख. सिम कार्ड या टॉप-अप सहायता सहित संचार सुविधाएं;
- ग. अनुरोध पर और पर्याप्त मंजूरी देने पर आसपास के शहरी केंद्रों तक परिवहन व्यवस्था;
- घ. मनोरंजक और सांस्कृतिक सहायता;
- ड. मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सहायता;
- च. चिकित्सा सहायता और सुविधा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और सहायता;
- छ. स्थानीय कानूनों, रीति-रिवाजों और आपातकालीन संपर्कों के बारे में जानकारी;
- ज. कल्याणकारी गैर सरकारी संगठनों और कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी।

65. **तट-आधारित कल्याण सुविधा के संबंध में सूचना का प्रसार।**
पत्तन बहुभाषी नोटिस, मानचित्र, डिजिटल प्लेटफॉर्म या अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से कल्याणकारी जानकारी प्रदान करेंगे।
66. **कौंसलर और उचित व्यवहार समर्थन।**
पत्तन सक्षम अधिकारियों के समन्वय से कौंसलर और उचित उपचार तंत्र तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे।
- ब. धारा 72 के तहत पत्तनों द्वारा निर्वहन किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत दायित्व।
67. **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत दायित्वों का अनुपालन।**
प्रत्येक पत्तन ऐसे कन्वेशन-संबंधी दायित्वों, जो उस पर लागू होते हैं और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, का पालन करेगा

अनुसूचियां और प्रपत्र

अनुसूची I-नमूना रसीद प्ररूप (नियम 11 देखें)

प्रमुख पत्तन प्राधिकरण - शुल्क/शुल्क की प्राप्ति

- रसीद संख्या:
- दिनांक और समय:
- भुगतानकर्ता/एजेंट का नाम:
- पोत का नाम / सकल टनभार / संदर्भ (यदि लागू हो):
- प्रभार की प्रकृति (खंड/टैरिफ कोड के साथ):
- सेवा का विवरण:
- राशि (₹):
- जीएसटी / कर (₹):
- प्राप्त कुल राशि (₹):
- भुगतान का तरीका:
- यूटीआर/टीएक्सएन आईडी और बैंक का नाम:
- जारीकर्ता (नाम, पद):
- हस्ताक्षर / डिजिटल प्रमाणीकरण:

अनुसूची II
(नियम 12 देखें)
पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं के लिए तकनीकी विनिर्देश

1. सामान्य कार्यक्षेत्र

अनुसूची I पत्तनों में पोर्ट रिसेप्शन सुविधाओं के लिए तकनीकी और प्रचालन अपेक्षाओं को परिभाषित किया गया है, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण पर किसी भी दिशानिर्देश के संबंध में लागू किया जाएगा।

2. तकनीकी और प्रचालन मानक

पीआरएफ में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित तकनीकी मानक शामिल होंगे:

- क. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुरूप सीवेज शोधन सुविधाएं, जिसमें जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, कुल निलंबित ठोस और कीटाणुशोधन से संबंधित अपेक्षाएं शामिल हैं;
- ख. एमएआरपीओएल कन्वेंशन के अनुसार अपशिष्ट धारा का पृथक्करण, जिसमें तैलीय अपशिष्ट, सीवेज, कचरा और खतरनाक या विशेष अपशिष्ट श्रेणियां शामिल हैं;
- ग. पोत यातायात और पीक बर्थ अधिभोग में अस्थायी वृद्धि को समायोजित करने के लिए सज हैंडलिंग क्षमता का प्रावधान;

3. प्रदर्शन मेट्रिक्स

4. पीआरएफ चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे और इस तरह से संचालित किए जाएंगे कि अपशिष्ट वितरण कार्यों के कारण होने वाली देरी को कम किया जा सके;

5. पीआरएफ को वार्षिक पर्याप्तता लक्ष्यों को पूरा करना होगा, जिसमें अपटाइम बेंचमार्क शामिल हैं, जैसा कि हरितसागर दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट किए जाएं।

6. उप-नियम (2) का प्रचालन ऐसे संशोधनों के अध्यधीन होगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हरितसागर दिशानिर्देशों के किसी भी संशोधन, संशोधन या अधिक्रमण के अनुसरण में अपेक्षित हो।

7. हरित संक्रमण अवसंरचना

8. पीआरएफ, जहां लागू हो, में निम्नलिखित के लिए अवसंरचना शामिल होगी:

- क. वैकल्पिक ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट और अवशेषों की सुरक्षित हैंडलिंग और प्रबंधन;
- ख. तट बिजली प्रणालियों से उत्पन्न अपशिष्ट की प्राप्ति और प्रबंधन, जिसमें ट्रांसफार्मर तेल और संबंधित विद्युत अपशिष्ट शामिल हैं;
- ग. स्पिल रिस्पांस अवशेषों सहित वैकल्पिक ईंधन बंकरिंग संचालन से उत्पन्न अपशिष्ट और अवशेषों का प्रबंधन।

फॉर्म - एडब्ल्यूएन-1
(नियम 21 देखें)
अग्रिम अपशिष्ट सूचना (एडब्ल्यूएन)

1. जलयान का विवरण

- जलयान का नाम: _____
- आईएमओ सं.: _____
- ध्वज: _____
- जलयान का प्रकार: _____
- जीटी/ डीडब्ल्यूटी: _____

2. पोर्ट ऑफ कॉल विवरण

- अंतिम पोर्ट ऑफ कॉल: _____
- अगला पोर्ट ऑफ कॉल: _____
- ईटीए (स्थानीय समय): _____
- ईटीडी (स्थानीय समय): _____

3. अपशिष्ट ऑनबोर्ड (मार्पोल अनुबंध-वार)

- अनुबंध I (तेल युक्त अपशिष्ट): _____
- अनुबंध II (एनएलएस अवशेष): _____
- अनुबंध IV (सीवेज): _____
- अनुबंध V (कचरा श्रेणियां क-छ): _____
- अनुबंध VI (स्कबर वॉश पानी के अवशेष/ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ): _____

4. पत्तन पर छोड़े जाने वाला अपशिष्ट

(प्रकार और मात्रा निर्दिष्ट करें)

5. जलयान पर रखा गया अपशिष्ट**6. अंतिम अपशिष्ट निर्वहन (पत्तन और तिथि)****7. रिसेप्शन सुविधा के लिए अनुरोध**

हाँ नहीं

आवश्यक सुविधा का प्रकार: _____

8. मास्टर द्वारा प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है.

- मास्टर का नाम: _____
- हस्ताक्षर: _____
- दिनांक: _____

अनुसूची III
(नियम 24 देखें)
अपशिष्ट वितरण दायित्वों से छूट प्रदान करने के लिए शर्तें और मापदंड

1. भंडारण क्षमता का प्रदर्शन

मास्टर जानकारी प्रस्तुत करेगा जिसमें यह बताया गया हो कि जलयान में जलयान-जनित अपशिष्ट के लिए पर्याप्त समर्पित भंडारण क्षमता है, जिसमें शामिल हैं:

- क. अपशिष्ट श्रेणी द्वारा अधिकतम अनुमोदित भंडारण क्षमता;
- ख. वर्तमान में जलयान पर कचरे की मात्रा;
- ग. अगले पोर्ट ऑफ कॉल तक अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन; और
- घ. बरकरार रखी गई सुरक्षा का मार्जिन

2. अगले पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं के साक्ष्य

मास्टर अगले पोर्ट ऑफ कॉल की पहचान करेगा और निम्नलिखित प्रदान करेगा:

- क. पत्तन पर प्रासंगिक पत्तन रिसेप्शन सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि, के आधार पर:
- ि. आईएमओ वैश्विक एकीकृत पोत परिवहन सूचना प्रणाली पर प्रकाशित सूचना; या
- ii. अगले पोर्ट परिवहन ऑफ कॉल के पत्तन प्राधिकरण के आधिकारिक प्रकाशन; और
- ख. अगले पत्तन पर इच्छित डिलीवरी योजना।

3. यात्रा जोखिम कारक

छूट का आकलन करने में, संरक्षक को निम्नलिखित का उचित ध्यान रखना होगा:

- क. यात्रा की लंबाई और प्रकृति;
- ख. जलयान और प्रणोदन प्रणाली का प्रकार;
- ग. साथ ले जाए गए माल की प्रकृति; और
- घ. उच्च प्रदूषण संकट प्रस्तुत करने वाली अपशिष्ट श्रेणियां।

4. संतुष्टि की रिकॉर्डिंग

नियम 26(2) के तहत दी गई कोई भी छूट लिखित रूप में दर्ज की जाएगी और इसमें शामिल होंगे:

- क. सम्मिलित की गई अपशिष्ट श्रेणियां;
- ख. छूट दी गई मात्रा;
- ग. निर्दिष्ट यात्रा या पोर्ट कॉल तक सीमित वैधता; तथा
- घ. अनुदान को कारण।

नॉन-डिरोगेशन

इस अनुसूची में कुछ भी एमएआरपीओएल कन्वेंशन के उल्लंघन में समुद्र में पोत-उत्पन्न अपशिष्ट के किसी भी प्रवाह की अनुमति देने के रूप में नहीं माना जाएगा।

फॉर्म- सीपीआईआर-1
(नियम 36 देखें)
तटीय प्रदूषण की घटना की रिपोर्ट

1. जलयान/ सुविधा विवरण

- जलयान का नाम: _____
- आईएमओ सं.: _____
- ध्वज: _____
- एजेंट: _____

2. प्रदूषण संकट का प्रकार

- तेल/तैलीय मिश्रण/कीचड़
- हानिकारक तरल पदार्थ
- रासायन / एचएनएस
- अपशिष्ट
- कचरा (थ्रेणी निर्दिष्ट करें)
- अन्य हानिकारक पदार्थ: _____

3. विमुक्त/ संकट की अनुमानित मात्रा**4. स्थान (निर्देशांक/बर्थ)****5. घटना का समय****6. कारण (यदि ज्ञात हो)****7. की गई कार्रवाई**

- तैनात कंटेनरमेंट बूम
 प्लग किए गए स्कूपर्स
 बंद किए गए पंप
 एक्टिवेटेड आपातकालीन प्रदूषण नियंत्रण
 टर्मिनल या पोर्ट को सूचना

8. प्रभाव आकलन (तटीय जल / मत्स्य पालन / समुद्री जीवन):**9. संलग्नक**

- फोटो/वीडियो
- लॉग अर्क
- ध्वनि रिकॉर्ड
- टैक डेटा

10. मास्टर द्वारा प्रमाणन

मैं प्रमाणित करता हूं कि प्रदान की गई जानकारी सत्य है।

नाम: _____ हस्ताक्षर: _____
 दिनांक: _____

फॉर्म I
(नियम 40 देखें)
पत्तन की ओर जाने वाले नौगम्य नदियों या नहरों की अधिसूचना के लिए प्रपत्र

1. अधिसूचना का शीर्षक

(नदी/चैनल के निर्दिष्ट खंड को इंगित करने वाला संक्षिप्त वर्णनात्मक शीर्षक)

2. नदी/चैनल का विवरण जिसे नौगम्य प्रवेश मार्ग घोषित किया गया है

(क) पत्तन की ओर जाने वाली नदी/चैनलों का नाम:

(ख) भौगोलिक निर्देशांक और कोई अन्य घटक, जैसा भी लागू हो:

- अक्षांश: _____ देशांतर: _____

3. नौवहन सहायता और मार्किंग (जैसा लागू हो):

4. अधिसूचना का प्रयोजन:

5. निर्देशन (यदि कोई हो):

6. प्रारंभ की तिथि:

अधिसूचना _____ से लागू होगी

7. अधिसूचना जारी करने वाला प्राधिकारी:

विभाग/ मंत्रालय का नाम: _____

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

मुहर: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

नोट (राजपत्र प्रिंटर / पत्तन प्राधिकरण उपयोग के लिए)

- भरे हुए फॉर्म को आधिकारिक राजपत्र में शब्दश: प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- इस फॉर्म का एक डिजिटल संस्करण सरकार और संबंधित पत्तन वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

फॉर्म II
(नियम 45 देखें)
नए पत्तन की अधिसूचना के लिए प्रपत्र

1. अधिसूचना का शीर्षक

2. नए पत्तन का नाम

3. पत्तन सीमाओं का भू-स्थानिक विवरण

(क) भूमि की सीमा (यदि लागू हो)

विवरण और निर्देशांक:

(ख) समुद्राभिमुख की सीमा

निर्देशांक:

- बिंदु 1: अक्षांश _____ देशांतर _____
- बिंदु 2: अक्षांश _____ देशांतर _____
- बिंदु 3: अक्षांश _____ देशांतर _____

(आवश्यकतानुसार अन्य अंक जोड़े जा सकते हैं)

(ग) पत्तन की और जाने वाले चैनल और नौचालन पहुंच के लिए अग्रणी चैनल:

4. हाइड्रोग्राफिक और नौचालन विशेषताएं:

(आवश्यकतानुसार चार्ट/मानचित्र संलग्न करें)

5. उद्देश्य और प्रयोज्यता:

(पत्तन कार्यों: कार्गो हैंडलिंग, यात्री संचालन, अपतटीय टर्मिनल, आदि का वर्णन करें)

6. अधिसूचना की प्रभावी तिथि:

7. जारीकर्ता प्राधिकारी:

नाम: _____

पदनाम: _____

विभाग: _____

हस्ताक्षर: _____

मुहर: _____

दिनांक: _____

स्थान: _____

प्रस्तुति 3
(नियम 45 देखें)
वर्तमान पत्तन सीमाओं में परिवर्तन के लिए प्रपत्र

1. अधिसूचना का शीर्षक:

2. पत्तन का नाम:

3. परिवर्तन की प्रकृति:

- सीमाओं का विस्तार
 सीमा में कमी
 निर्देशांक का परिवर्तन
 पत्तन/एंक्रेज की ओर जाने वाले नए चैनलों का समावेशन
 क्षेत्र का बहिष्करण
 अन्य (निर्दिष्ट करें): _____

4. पत्तन सीमाओं के परिवर्तित निर्देशांक:

5. परिवर्तन का औचित्य:

(विस्तार: ड्रेजिंग, नए टर्मिनल; प्रतिबंध: सुरक्षा, पर्यावरण क्षेत्र, आदि)

6. संलग्न मानचित्र/चार्ट:

7. प्रभावी तिथि:

8. जारीकर्ता प्राधिकारी:

नाम: _____
पदनाम: _____
हस्ताक्षर: _____
मुहर: _____
दिनांक: _____
स्थान: _____

[फा. सं. 24015/1/2025-पीडी-1 (ई – 378148)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2026

G.S.R. 58(E).—Draft rules proposed to be made by (i) the Central Government in exercise of the powers conferred under section 76(2) read with section 7(2), 18(2), 18(3), 18(6), 20(5), 24(2), 26(2), 48(2), 54(2), 72; and (ii) the Central Government in consultation with the State Governments, in exercise of the powers conferred under section 78(2) read with sections 1(3)(a)(iii), 11(2), 36, 38(1), 38(3), 39, 40(1), 40(2), 42(1), 44(1), 49, 67, 68 of the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025), on or after the date of coming into force of the said Act, are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after **22nd February, 2026**.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Naveen Kumar, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Room No. 547, 5th Floor, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi – 110001 or by email at (uspd-psw@gov.in and sopd1-psw@gov.in) on or before the 22nd February, 2026.

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall not be attributed publicly to the persons submitting the same and shall be held in a fiduciary capacity, to enable stakeholders to provide their views freely, and shall be duly considered by the Central Government before finalisation of the rules.

DRAFT RULES

CHAPTER I - PRELIMINARY

1. Short Title, Commencement and Applicability.

1. These rules may be called the Indian Port Rules, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. Chapter I shall be applicable to all ports to which the Act applies, whereas other Chapters under these rules shall apply to ports in such manner:
 - a. to major ports, all rules, made hereunder;
 - b. rules made under section 78(2) i.e., rules 12 to 46, rule 55, rules 57 to 66 and rule made under section 76(2) i.e., rule 67.

2. Definitions.

In these rules, unless the context otherwise requires—

- a. “Act” means the Indian Ports Act, 2025 (27 of 2025);
- b. “Advance Waste Notice” or “AWN” means the pre-arrival declaration containing information on waste held on board and waste intended to be discharged at the port, submitted under section 39 of the Act, in accordance with these rules;
- c. “agent” means the agent as defined under section 3(3) of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

- d. “arrival report” means the information required to be furnished by the owner, agent or master of a vessel under section 49 of the Act and in accordance with these rules;
- e. “auditing authority” means the authority or any person, body, or agency authorised by the authority or the Central Government to conduct an audit under these rules;
- f. “corrective action plan” means the plan prescribed under rule 33 of these rules and is a plan produced in response to the audit observations, deficiencies, and which contains pathways for rectifications identified in accordance with the scope of the audit;
- g. “designated incident reporting officer” means the deputy conservator or an officer of equivalent rank, at the port;
- h. “designated system” means the maritime single window or any other electronic system, designated by the Central Government;
- i. “expenses” means the reasonable costs, charges, and expenditures which, under section 26(2) of the Act, may include:
 - i. repair or replacement costs,
 - ii. temporary works and emergency measures,
 - iii. professional and survey fees, and
 - iv. other related costs as provided in these rules;
- j. “health officer” means the officer appointed under section 24 of the Act;
- k. “incident” means any incident referred to in section 67 of the Act;
- l. “maritime single window” means a digital platform which enables, inter alia, submission of standardised information and documents for fulfilment of port and ship reporting formalities in accordance with the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965;
- m. “navigable river or channels leading to such port” means any river, estuary, backwater, creek, canal, fairway, channels, or other waterway which-
 - i. is, or is intended to be, regularly used by vessels navigating to or from a port; and
 - ii. lies outside, or partly outside, the port limits as notified under section 11(1);
- n. “national perspective plan” means the plan formulated by the Central Government under section 12(1) of the Act;
- o. “owner of the obstruction” means the person who holds the relevant permit, grant, licence or other lawful instrument issued by the Government under which the obstruction is established or maintained, and includes any concessionaire, lessee, or operator who is responsible, under contract or law, for the maintenance and safety of such obstruction;
- p. “pollution incident” means any occurrence, event, or condition arising out of a vessel, port facility or operations within port limits that results in or is likely to result in:
 - i. discharge, escape, leakage or spillage of oil, oily mixture, oily residue;
 - ii. discharge or threat of discharge of noxious liquid substances;
 - iii. discharge or threat of discharge of harmful substances under MARPOL;
 - iv. release of sewage, garbage, plastics, chemicals or waste harmful to the marine environment;
 - v. any condition posing a risk to:
 - a. the health of the coastal population and users of coastal waters;
 - b. fisheries and other living marine resources;
 - c. coastal and port installations, facilities and services;

- d. tourist attractions, amenities and other economic interests of the coastal area; or
- e. the conservation of marine and coastal ecosystems.
- vi. threat to life or property or the environment;
- q. “port waste reception and handling plan” or “plan” means a plan prepared and implemented under section 38 of the Act;
- r. “receipt” means a formal acknowledgement issued as proof of payment of fees or other charges in accordance with section 48 of the Act;
- s. “shore-based welfare facilities and services” means the facilities and services contemplated under Regulation 4.4 of the Maritime Labour Convention, 2006 and detailed in the DG Shipping Welfare Guidelines as updated from time to time;
- t. “Waste Delivery Receipt” or “WDR” means receipt issued by a port acknowledging receipt of waste from a vessel by a reception facility in accordance with section 40(2).

CHAPTER II – ADMINISTRATION

A. Salary and allowances and other conditions of service under section 7(2)

3. Appointment.

1. The Council may ordinarily be staffed by officers and employees made available or deputed by the Central Government under section 7(1) of the Act.
2. The pay, allowances, and other conditions of service of the officers and employees of the Council appointed through deputation under sub-rule (2) shall be regulated in accordance with the applicable Parent Cadre Service Rules or Central Government rules and the allowances admissible to the corresponding grades, as revised or amended from time to time.

B. Other officers of the port to be appointed under section 18(2) and the terms and conditions of their service under section 18(3)

4. Appointment of other officers at the port.

1. Every port may, in addition to a conservator and harbour master, appoint officers to discharge duties provided under sub-rule (2).
2. The officers appointed under sub-rule (1) shall discharge functions relating to marine operations, prevention and containment of pollution, safety and any other functions under the Act.
Provided that one or more officers may be assigned to discharge all or any such functions or parts thereof.
3. The appointment to the posts of port officers shall be as per recruitment regulations of the port unless directed otherwise in this behalf by the Central Government.

5. Pay and allowances of port officers.

The pay and allowances of port officers under this rule shall be as determined by the Central Government.

6. Conditions of service of port officers.

The other conditions of service of port officers such as leave, tenure, probation, resignation, retirement and superannuation, working hours, promotion, seniority, conduct and disciplinary proceedings shall be as per service regulations of the port unless directed otherwise in this behalf by the Central Government.

7. Power to relax rules in relation to classification, appointment and eligibility of other officers.

The Central Government may relax any provision of these rules for a class or category of officers for reasons recorded in writing.

C. Powers to be delegated by the conservator and the persons to whom such powers may be delegated under section 18(6)**8. Delegation of powers of the conservator.**

1. The conservator may delegate to any officer(s) all or any of its powers, duties, and functions under the Act.
2. Any authorisation under sub-rule (1) above shall be:
 - a. in writing;
 - b. specify the nature and extent of delegation in each case; where the conservator is a body of persons, be passed by a general or special resolution of such body.
3. The conservator retains the right to revoke, vary, or suspend the delegation of power, at any time, without assigning any reason, if deemed necessary in the interest of port safety, security or for any other reason, to be recorded in writing.

D. Qualifications, experience and other terms and conditions of service of the health officer under section 24(2)**9. Method of appointment and conditions of service of health officer.**

1. There shall be a health officer for every major port.
2. The health officer shall possess such qualification, experience and be subject to such other terms and conditions of service as may be prescribed by the Central Government for Port Health Organisation.
3. The Health Officer shall discharge all health-related functions at the port as are assigned under the Act or by directions of the Central Government, including compliance with International Health Regulations, 2005.

E. Form and manner of receipt of fees or other charges under section 48(2)**10. Obligation to issue receipt.**

Every authorised officer under section 48 of the Act to collect any fee or other charge shall issue a receipt acknowledging such payment.

11. Form and manner of issuance of receipt.

1. All receipts issued shall contain particulars specified in Schedule I.
2. A duplicate receipt may be issued upon written request of the payer, supported by identification and payment proof.
3. All receipts shall be maintained for a minimum period of seven years.
4. The authority may specify formats, digital templates, or standard operating procedures for issuance of receipts.

CHAPTER III- POLLUTION

F. The conditions subject to which port shall provide reception facilities under section 36

12. Establishment and adequacy of port reception facilities.

1. Every port shall establish, operate and maintain port reception facilities which are adequate to meet the needs of vessels normally using the port, without causing undue delay, having regard to-
 - a. the size, type and traffic profile of vessels calling at the port;
 - b. the nature, frequency and quantity of vessel-generated waste ordinarily delivered; and
 - c. operational characteristics of the port, including berth configuration, terminal layout and cargo handled.
2. Port reception facilities shall be capable of receiving, segregating and handling, as applicable, vessel-generated waste and residues in accordance with-
 - a. Annex I (oil, oily mixtures, sludge, bilge water, tank washings and exhaust gas cleaning system residues);
 - b. Annex II (residues and mixtures containing noxious liquid substances);
 - c. Annex IV (sewage, including treated and untreated black water and grey water);
 - d. Annex V (garbage, segregated by category, including plastics, food waste, operational waste, cargo residues and e-waste); and
 - e. Annex VI (ozone-depleting substances, exhaust gas cleaning system residues and other air pollution control residues) of the MARPOL Convention.
3. Where applicable, port reception facilities shall also be adequate to receive ballast water and sediments in accordance with Article 5 of the Ballast Water Management Convention, having regard to port side obligations and the availability of approved ballast water management systems on board vessels.
4. For the purposes of sub-rules (2) and (3), adequacy of port reception facilities shall be assessed having regard to the following technical and operational parameters, namely:
 - a. capacity, including sufficient storage, treatment or transfer capability to handle waste volumes ordinarily generated between successive ports of call;
 - b. availability, including operating hours, response time and ability to receive waste upon reasonable notice;
 - c. accessibility, including safe and practicable access at berths, anchorages or terminals without interfering with vessel operations;

- d. segregation and compatibility, ensuring that different categories of waste are handled separately and in a manner compatible with downstream treatment or disposal systems;
 - e. environmental and safety controls, including spill prevention, containment, occupational safety and emergency response arrangements; and
 - f. interface with vessels, including compatibility with standard shipboard discharge arrangements, hoses, couplings and connection points.
5. Port reception facilities shall be planned and operated on the basis of a demand-responsive approach, having regard to the information through AWNs, historical data on waste deliveries, any complaints or reports of alleged inadequacy of facilities and any changes in vessel technology, fuel types, emission control systems or waste streams.
6. Without prejudice to sub-rules (2) to (5), port reception facilities shall, as far as practicable, be capable of receiving:
- a. wastes arising from the use of alternative fuels, shore power systems and emission-abatement technologies; and
 - b. any additional categories of vessel-generated waste as may be notified by the Central Government, having regard to technological developments and international standards.
7. Nothing in this rule shall be construed as requiring a port to provide identical facilities for waste at every berth, provided that adequate and effective arrangements exist to ensure reception of vessel-generated waste without undue delay and without risk of unlawful discharge into the sea.
8. The design, construction and operation of port reception facilities shall conform to the technical and operational standards specified in Schedule II.

G. Form and manner of preparing port waste reception and handling plan under section 38(1)

13. Form and manner of plan.

1. The Port Waste Reception and Handling plan made in accordance with section 38(1) of the Act, shall, at minimum, contain the following -
 - a. an assessment of the need for waste reception facilities, in the light of the need of the ships normally visiting the harbour or terminal;
 - b. a description of the types and capacity of waste reception facilities;
 - c. a detailed description of the procedures for the reception and collection of prescribed wastes;
 - d. a description of the charging system, if any;
 - e. procedures for ongoing consultations with persons using the harbour or terminal, waste contractors and other interested parties;
 - f. the type and quantities of specified wastes received and handled;
2. The plan may also include:
 - a. a summary of relevant legislation and formalities for delivery;
 - b. identification of a person or persons to be responsible for the implementation of waste management plan;
 - c. a description of the pre-treatment equipment and processes in the harbour or terminal, if any;
 - d. a description of methods of recording amounts of specified wastes received;
 - e. a description of how the specified wastes are disposed of.
3. The plan may also include information to be made available to all harbour or terminal users:

- a. a brief reference to the fundamental importance of proper delivery of specified wastes;
 - b. the location of waste reception facilities applicable to each berth, with a diagram or map;
 - c. list of specified wastes normally dealt with;
 - d. list of contact points, the operators and the services offered;
 - e. description of procedures for delivery;
 - f. description of charging system, if any; and
 - g. procedures for reporting alleged inadequacies of waste reception facilities.
4. The port may prepare the plan in consultation with stakeholders, including agents and may consider the maximum amount of waste that could be received.
 5. After the approval of the Board, the plan shall be submitted to the Central Government, at the first instance and at every instance within three months of significant changes.
 6. The plan may be prepared and maintained in electronic form, aligned with relevant formats adopted by the IMO.

14. Review and availability of the plan.

1. The plan may be reviewed every two years by the authority.
2. The plan shall be made available to port users preferably electronically or in such manner as the authority may determine.

H. The information about the port waste reception and handling plan and manner of communicating of such information under section 38(3)

15. Information to be communicated to vessels in relation to the plan.

For the purposes of sub-section (3) of section 38, every port shall ensure that the following minimum information from its approved port waste reception and handling plan is communicated to vessels normally using that port:

- a. particulars of the port and plan in accordance with rule 13.
- b. contacts and emergency information—
 - i. list of relevant contact points;
 - ii. contact details of environmental or health officers responsible for waste-related incidents.
- c. complaint and feedback mechanism—
 - i. procedure for vessels to lodge any complaints on alleged inadequacy or unavailability of reception facilities, with reference, where applicable, to the IMO reporting format and the designated contact point;
 - ii. indication of how complaints will be acknowledged and addressed.
- d. environmental and safety requirements—
 - i. any port-specific environmental or occupational safety requirements applicable during delivery of waste, including personal protective equipment, traffic control and spillage prevention measures;
 - ii. description of any local prohibitions or sensitive areas relevant to waste transfer operations.

16. Manner of communication of plan.

The information referred to in rule 15 shall be communicated preferably electronically or in such manner as the port authority may determine.

17. Updates to plan.

The information made available under rule 15 may be kept updated as far as practicable by the port authority to reflect material changes in the port waste reception and handling plan.

18. Maintenance of records in relation to information contained in plan.

Every port shall maintain, for a period of not less than five years:

- a. copies showing the information communicated at different points in time;
- b. records of any complaints received in relation to the adequacy, accessibility or clarity of information on port reception facilities, and actions taken thereon.

J. Form, manner and time for submitting an advance waste notice under section 39**19. Obligation to submit AWN.**

1. Every vessel intending to call at a port shall submit an AWN to the port of call.
2. The AWN shall be submitted irrespective of whether the vessel:
 - a. intends to discharge waste;
 - b. has no waste to discharge; or
 - c. wishes to retain all waste on board.

20. Time for submission of the AWN.

1. An AWN shall be submitted:
 - a. at least 24 hours before the vessel's arrival; or
 - b. if the voyage is less than 24 hours, at the time of departure from the previous port; or
 - c. if the port of call becomes known less than 24 hours in advance, as soon as the information becomes available.
2. Any material change in the information submitted may be updated as soon as practicable.

21. Form of AWN.

The AWN shall be provided in alignment with Form AWN-1, as specified under these rules.

22. Manner of submission of AWN.

The AWN shall be submitted in such manner, preferably by electronic means, as may be specified by the port authority.

23. Record keeping of AWN.

1. The port shall maintain records of AWNs for administrative and audit purposes, in such manner as it may determine.

2. AWNs shall be made available to any stakeholder as determined by the port authority.

K. Conditions for delivery of vessel-generated waste under section 40(1)

24. Waste delivery obligations.

1. Unless exempted under sub-rule (2), the master of a vessel calling at a port shall ensure that all vessel-generated waste which cannot be lawfully discharged into the sea in accordance with the provisions of the MARPOL Convention is delivered to an appropriate port reception facility before the vessel departs from the port.
2. A port may exempt a vessel, in whole or in part, from the obligation referred to in sub-rule (1), where the master demonstrates to the satisfaction of the conservator or such appointed authorised person, in accordance with the parameters specified in Schedule III that such conditions are met, and where such satisfaction is duly recorded in writing:
 - a. the vessel has sufficient dedicated and segregated storage capacity for all vessel-generated waste remaining on board and expected to be generated until the next port of call, so as to continue the voyage without any discharge into the sea in contravention of the MARPOL Convention; and
 - b. adequate and suitable port reception facilities for the relevant categories of vessel-generated waste are available at the next port of call, taking into account information published through the IMO Global Integrated Shipping Information System or such other reliable and publicly accessible sources as may be recognised by the Central Government.
3. Any exemption granted under sub-rule (2) shall be recorded in writing and retained by the port in such manner as it may determine for audit purposes.
4. In situations of temporary overloading, malfunction, or unavailability of port reception facilities, the conservator shall, as far as practicable—
 - a. prioritise vessels which, having regard to their type, cargo, fuel, or waste characteristics, present a higher risk of marine pollution;
 - b. coordinate with nearby ports and competent authorities, as appropriate authorised waste reception operators, and other competent authorities to make alternative reception arrangements; and
 - c. ensure that any delay or alternative arrangement does not result in the unlawful discharge of vessel-generated waste into the sea.

L. Form and manner of issuance of waste delivery receipt under section 40(2)

25. Obligation to issue WDR.

1. Every reception facility shall issue a WDR upon receiving waste from a vessel.
2. A copy of the WDR shall be provided to:
 - a. the master,
 - b. the agent of the vessel, and
 - c. the port/authority.

26. Form of WDR.

1. The WDR shall be issued in accordance with particulars prescribed under this rule;
2. The form shall include:
 - a. vessel particulars, including name and IMO number;
 - b. waste categories delivered, referenced Annex-wise under MARPOL Convention;
 - i. Annex I: Oily waste/sludge/bilge
 - ii. Annex II: Noxious liquid residues
 - iii. Annex IV: Sewage
 - iv. Annex V: Garbage categories A–G
 - v. Annex VI: Exhaust gas cleaning residues
 - c. quantity of waste delivered, including the unit of measurement;
 - d. details of the port reception facility receiving the waste;
 - e. date and time of delivery;
 - f. status of receipt of waste, including acceptance or rejection, in whole or in part;
 - g. confirmation of receipt and onward handling or transfer of waste, as applicable; and
 - h. authentication by the port reception facility and the master or authorised officer of the vessel.

27. Manner of issuance of WDR.

1. A WDR may be issued preferably electronically or in physical form.
2. The WDR shall be issued within one hour of completion of waste discharge from vessels. In the event that the receipt is not issued within one hour, the delay and the reasons thereof shall be recorded in writing.
3. All quantities in a WDR shall be expressed in metric units, and decimal notation shall be used consistently.
4. The WDR shall be completed in English, and a translation in any additional language may be provided for convenience; in case of inconsistency, the English text shall prevail.

28. Multiple or partial deliveries of waste.

Where waste is delivered in more than one batch, separate WDRs may be issued.

29. Record-keeping requirements in relation to WDRs.

The reception facility shall maintain digital or physical records of all WDRs and may share with any stakeholders as it may be required.

30. Integration with portal in relation to WDRs.

The port or reception facility provider shall ensure that all data fields required to be uploaded in respect of the WDR are completed accurately and in a timely manner in accordance with section 43 of the Act.

M. Intervals and manner of conducting audit of ports under section 42(1)

31. Audit areas.

The audit shall be carried out for the purposes of checking the availability and adequacy of reception facilities and shall include audit of such pollution containment equipment as may be specified by the Central Government, and may include but not be limited to:

- a. adequacy and operational status of Port Reception Facilities for Annexes I, II, IV, V and VI of the MARPOL Convention;
- b. implementation and effectiveness of the plan;
- c. compliance with national environmental norms for disposal of waste received from vessels;
- d. compliance and operational readiness, to the extent applicable to port-side facilities and obligations in accordance with Ballast Water Management Convention.

32. Frequency of audits.

1. Every port shall undergo an audit at least once in every two years, in accordance with the standards as may be notified by the Central Government from time to time and in accordance with the guidelines issued by Director General of Maritime Administration.
2. Such biennial audit shall be conducted by a duly authorised auditor of Director General of Maritime Administration.

33. Reporting format and documentation for audit.

1. The audit report shall be submitted by the auditing authority to the Central Government and shall include the following:
 - a. brief summary of the port's overall compliance level;
 - b. time-bound corrective action plan, responsible parties, and proposed completion dates:
 - i. not exceeding 90 days, and detailing the immediate action that needs to be undertaken;
 - ii. or such extended period as may be permitted by the auditing authority for reasons to be recorded in writing.

34. Data management and confidentiality in relation to audits.

The port shall, for the purposes of the audit conducted under section 42 of the Act, facilitate the audit process by providing access to such information and records as is required to be maintained under this Act and the rules made thereunder, and shall retain the audit report and related records for at least 7 years.

N. Manner of reporting incidents under section 44(1)

35. Obligation to report pollution incidents.

Every port shall report to the Government any actual or threatened pollution incident within port limits, as soon as practicable after becoming aware of such incident.

36. Time for reporting of pollution incidents.

1. For every report under rule 35:
 - a. the master shall make an initial verbal report without delay, and in any case within 15 minutes of detection.
 - b. a written report in Form CPIR-1 shall be submitted by the port within 2 hours of the incident, or as soon as practicable if containment measures are ongoing.
 - c. a detailed supplementary report shall be submitted by the port within 24 hours if any further information becomes available subject to any such inquiries that the port may conduct with all relevant stakeholders.

37. Manner of reporting of pollution incidents.

1. The initial verbal report under rule 36 shall be made to—
 - a. VTS/Port Control on the designated VHF channel; or
 - b. the designated port officer on the emergency pollution hotline;
 - c. Directorate General of Maritime Administration Communication (DGCOM) Centre in case of discharge, escape, leakage or spillage of oil, oily mixture, oily residue.
2. The written report under rule 36 shall be submitted—
 - a. through the Port Community System (PCS) or Maritime Single Window; or
 - b. via the port's online pollution reporting portal; or
 - c. by email to the designated pollution reporting address.
3. If electronic submission is unavailable, a signed physical copy must be submitted to the conservator within 3 hours of system restoration.

38. Use of electronic portal.

The Central Government may, for the purposes of these rules, specify an electronic or other communication mechanism for reporting pollution incidents under this rule.

CHAPTER IV- MISCELLANEOUS**O. Form and the manner of notification of any part of the navigable rivers or channels leading to ports under section 1(3)(a)(iii)****39. Objectives and guiding principles in relation to notification of a navigable river.**

1. While notifying a navigable river or channels leading to such port under rule 40, regard shall be had to the following objectives and principles, namely:
 - a. to ensure that the spatial extent of the Act's application to navigable rivers or channels leading to such port is clearly and precisely defined for purposes of safety, navigation, environmental protection and levy of fees and charges;
 - b. to secure consistency between port limits, channels leading to such port and adjoining navigable waterways, and to avoid ambiguity or overlap in jurisdiction among authorities.

40. Form of notification of navigable rivers or channels leading to a port.

The form shall contain the particulars as specified in Form I.

41. Manner of publication of notification in relation to navigable rivers.

1. Every notification shall be—
 - a. published in the Official Gazette of the Government;
 - b. uploaded on the Official website of the Government;
 - c. The port may communicate the notification electronically to such authorities, as it may deem fit.

42. Interpretation in relation to notification of navigable river.

Where any question arises as to the interpretation of a notification issued under rule 40, the decision of the Central Government shall be final.

P. Norms, form and manner of notifying a new port and altering port limits under section 11(2)

43. Norms for declaration of a new port.

1. A new port shall be declared only where the proposal satisfies the following norms, namely:
 - a. Strategic and economic justification: There is demonstrable requirement for additional port capacity or specialised facilities in the region, having regard to:
 - i. projected cargo and passenger demand and hinterland connectivity;
 - ii. the national perspective plan and any regional or sectoral plans derived therefrom; and
 - iii. the potential to improve logistics efficiency, reduce turnaround time and support national development priorities;
 - iv. proposal is supported by a preliminary assessment of financial viability, including capital and operating cost estimates and possible funding sources.
 - b. Non-duplication and complementarity: the proposed new port does not result in unnecessary duplication of capacity in close proximity to existing ports, and, where multiple ports exist in a region, the proposal indicates how the new port will complement and not materially impair the viability of existing facilities except, where justified in the wider public interest.
 - c. Security and defence considerations: the location and intended operations of the proposed port are consistent with national security, coastal security, and defence considerations, and the proposal incorporates the views of the competent security and defence authorities.
 - d. The Central Government may for reasons to be recorded in writing, relax one or more of the norms specified in sub-rule (1) in exceptional cases where strategic, security or other public interest considerations so warrant.

44. Norms for alteration of port limits.

Prior to notifying alteration of port limits, the Government shall ensure:

- a. strategic and economic justification;
- b. security and defence considerations;

- c. navigational safety impact;
- d. maritime zoning;
- e. environmental protection; and
- f. any other norm as the Government may specify.

45. Manner of notification of new port and alteration of port limits.

Every notification declaring a new port and every notification altering port limits shall be published in the Official Gazette, in the forms specified in Form II and Form III, respectively.

46. Interpretation of notification of new port and alteration of port limits.

Where any question arises as to the interpretation of notification of new port or alteration of port limits, the decision of the Central Government shall be final.

Q. Manner of removal or alteration of obstruction and factors for determining compensation under section 20(5)

47. Objectives and guiding principles in relation to removal or alteration of lawful obstruction.

The removal or alteration of any obstruction shall be planned and conducted to:

- a. ensure navigational safety;
- b. protect port operations;
- c. minimise risk to life, property, and the environment;
- d. respect existing lawful rights of the owner of the obstruction, subject to the necessity of safeguarding navigation and port safety.

48. Consultation and notice to owner of lawful obstruction.

1. Where the obstruction exists, the conservator shall issue a written notice to such owner.
2. The conservator may, where appropriate and having regard to the urgency of the situation convene a consultation meeting or technical discussion with the owner of the obstruction and other concerned stakeholders; or seek the views of the relevant authority or other competent body.

49. Manner of removal or alteration of lawful obstruction.

The conservator shall, as far as practicable, adopt a manner of removal or alteration which:

- a. minimises the impact to the lawful owner of the obstruction;
- b. minimises disruption to vessel traffic and essential port services;
- c. seeks to avoid or reduce secondary environmental impacts; and
- d. is compatible with future development plans and designated uses of the port and waterway.

50. Emergency measures in relation to lawful obstruction.

1. Where an obstruction poses an immediate risk to the environment, life, navigation, port infrastructure, the conservator may, with reasons to be recorded in writing, take such urgent steps as are necessary.

2. The conservator shall, as soon as practicable after such emergency action, inform the owner of the obstruction, where identifiable, of the actions taken and reasons therefore, and proceed to determine compensation, if any, in accordance with the sub-rule (1).

51. Factors for determining compensation payable to the owner of lawful obstruction.

The determination of reasonable compensation shall be made having due regard to factors such as the age, design life, structural condition, and remaining service life of the obstruction at the time of removal or alteration, financial implications and such other relevant facts and circumstances of the case which shall be recorded in writing.

52. Documentation in relation to lawful obstruction.

1. The conservator may require the owner of the obstruction to submit relevant documents and data necessary for assessing compensation as early as possible and, in any case, without delay.
2. The conservator may seek the assistance of independent technical, financial or valuation experts to arrive at a reasoned recommendation on compensation.
 - **Factors to be considered by the conservator in determining the expenses to be paid under section 26(2)**

53. Objectives and guiding principles for determination of expenses.

1. Any person responsible for damage, destruction or loss caused to port or port facilities shall be liable to bear the full cost of restoring such property or facilities, as far as practicable, to the condition existing immediately prior to the incident, so that the authority does not incur any loss.
2. The conservator shall impose such costs on a proportionate basis and the responsibility shall lie with the person liable under sub-section (1) of section 26 to prove otherwise.

54. Inspection for assessment of loss, destruction or damage.

Depending on the nature, severity and technical complexity of the damage, the conservator may direct a preliminary inspection to be conducted to identify the nature and apparent extent of such loss or damage or detailed condition survey or engineering assessment to be undertaken, as the case may be.

S. Form, manner and time for reporting arrival of vessel at port under section 49

55. Obligation to submit vessel arrival report in accordance with Maritime Single Window.

The obligation to report an arrival under section 49 shall be in accordance with the Maritime Single Window or any other designated system as directed by the Central Government.

T. Manner of appointment of conservator from a body of persons under section 54(2)

56. **Appointment of person for imposition of penalty.**

For the purposes of sub-section (2) of section 54, the Board shall appoint a person from among such body of persons by way of a general or special resolution, as the case may be.

U. Manner of reporting of incidents under section 67

57. **Scope and obligation to report an incident.**

The designated incident reporting officer shall ensure that particulars of any incident under section 67 are obtained without delay from—

- a. owner, agent, or master of any vessel involved in the incident; and
- b. any terminal, facility or port service provider directly affected by, or involved in, the incident.

58. **Time and manner for reporting of incident by port.**

A written report under section 67 shall be submitted electronically to DGCOM as soon as reasonably practicable and in any event, no later than twenty-four hours from the time of the incident, including where the port is engaged in immediate response or safety operations, in such form, as may be directed by the Central Government.

59. **Register and record-keeping in relation to reporting of incident.**

Every port shall maintain an electronic incident register recording all incidents reported under the above rule, as well as all reports and any acknowledgements received thereof from DGCOM.

V. The provisions of shore based welfare services under section 68

60. **Standards for facilitation.**

Ports shall, for the purposes of facilitating compliance with section 68, have due regard to any Guidelines issued by the Director General of Maritime Administration.

61. **Non-discrimination at shore-based welfare facility.**

1. All shore-based welfare facilities and services shall be made available to seafarers without discrimination on any grounds of gender, nationality, race, colour, sex or any other status recognised under applicable law or international maritime labour standards.
2. Ports shall make appropriate arrangements, to ensure access to menstrual hygiene facilities for women seafarers.

62. **Accessibility and facilitation at port-based welfare facility.**

Ports shall endeavour to facilitate reasonable access to shore-based welfare services, having regard to security requirements, terminal location and operational constraints.

63. Remote and high-security terminals.

Where terminals are remote or subject to high security restrictions, the port shall specify adequate measures including transport arrangements to ensure meaningful access to seafarer welfare services.

64. Services at shore-based welfare facility.

Without prejudice to flexibility based on port size and traffic, shore-based welfare facilities and services having regard to regulation 4.4. of Maritime Labour Convention 2006 may include:

- a. internet connectivity;
- b. communication facilities including SIM cards or top-up assistance;
- c. transport arrangements to nearby urban centres on request and on grant of adequate clearance;
- d. recreational and cultural support;
- e. mental health counselling support;
- f. medical assistance and facilitation and emergency health services and support;
- g. information on local laws, customs and emergency contacts;
- h. information in relation to welfare NGOs and legal support.

65. Information dissemination in relation to shore-based welfare facility.

Ports shall provide welfare information through multilingual notices, maps, digital platforms or other appropriate means.

66. Consular and fair treatment support.

Ports shall facilitate access to consular and fair treatment mechanisms in coordination with competent authorities.

W. Obligations under international conventions to be discharged by the ports under section 72.**67. Compliance with obligations under international conventions.**

Every port shall comply with such convention-related obligations as are applicable to it and in accordance with the directions of the Central Government.

SCHEDULES and FORMS**Schedule I-Model Receipt Format***(See rule 11)***MAJOR PORT AUTHORITY – RECEIPT OF FEES/CHARGES**

- Receipt No.:
- Date and Time:
- Name of Payer / Agent:
- Vessel Name / Gross tonnage / Reference (if applicable):
- Nature of Charge (with clause/tariff code):
- Description of Service:
- Amount (₹):
- GST / Taxes (₹):
- Total Amount Received (₹):
- Mode of Payment:
- UTR/Txn ID and name of the bank:
- Issued By (Name, Designation):
- Signature / Digital Authentication:

SCHEDULE II
(See rule 12)
Technical specifications for port reception facilities

1. General Scope

Schedule I defines the technical and operational requirements for Port Reception Facilities in ports to which these rules apply, and shall be implemented having regard to any guidelines on renewable energy integration issued by the Central Government.

2. Technical and Operational Standards

PRFs shall include, inter alia, the following technical standards:

- a. sewage treatment facilities conforming to standards notified by the Central Pollution Control Board, including requirements relating to biochemical oxygen demand, total suspended solids and disinfection;
- b. segregation of waste stream in accordance with the MARPOL Convention, including oily waste, sewage, garbage and hazardous or special waste categories;
- c. provision for surge handling capacity to accommodate temporary increases in vessel traffic and peak berth occupancy;

3. Performance Metrics

- 4. PRFs shall be available on a round-the-clock basis and operated in a manner that minimises delays attributable to waste delivery operations;
- 5. PRFs shall meet annual adequacy targets, including uptime benchmarks, as may be specified under the Harit Sagar guidelines.
- 6. The operation of sub-rule (2) shall be subject to such modifications as may be required pursuant to any amendment, revision, or supersession of the Harit Sagar Guidelines, as issued by the Central Government from time to time.

7. Green Transition Infrastructure

- 8. PRFs shall, where applicable, include infrastructure for:
 - a. the safe handling and management of waste and residues arising from the use of alternative fuels;
 - b. the reception and management of waste arising from shore power systems, including transformer oils and related electrical waste;
 - c. the management of waste and residues arising from alternative fuel bunkering operations, including spill response residues.

FORM – AWN-1
(See Rule 21)
ADVANCE WASTE NOTICE (AWN)

1. Vessel Details

-
- Name of Vessel: _____
- IMO Number: _____
- Flag: _____
- Type of Vessel: _____
- GT / DWT: _____

2. Port Call Details

-
- Last Port of Call: _____
- Next Port of Call: _____
- ETA (Local Time): _____
- ETD (Local Time): _____

3. Waste Onboard (MARPOL Annex-wise)

-
- Annex I (Oily Waste): _____
- Annex II (NLS Residues): _____
- Annex IV (Sewage): _____
- Annex V (Garbage Categories A–G): _____
- Annex VI (Scrubber wash water residue/ ozone-depleting substances): _____

4. Waste to be Discharged at Port

(Specify type and quantity)

5. Waste Retained Onboard**6. Last Waste Discharge (Port and Date)****7. Request for Reception Facility** Yes No

Type of Facility Required: _____

8. Certification by Master

I hereby certify that the information provided above is true and complete.

-
- Name of Master: _____
- Signature: _____
- Date: _____

Schedule III*(See Rule 24)***Conditions and Parameters for Grant of Exemption from Waste Delivery Obligations****1. Demonstration of Storage Capacity**

The master shall furnish information demonstrating that the vessel has sufficient dedicated storage capacity for vessel-generated waste, including:

- a. maximum approved storage capacity by waste category;
- b. quantity of waste currently on board;
- c. estimated waste generation until the next port of call; and
- d. margin of safety retained.

2. Evidence of Next Port Reception Facilities

The master shall identify the next port of call and provide:

- a. confirmation of availability of relevant port reception facilities at such port, based on:
 - i. information published on the IMO Global Integrated Shipping Information System; or
 - ii. official publications of the port authority of the next port of call; and
- b. the intended delivery plan at the next port.

3. Voyage Risk Factors

In assessing exemption, the conservator shall have due regard to:

- a. length and nature of the voyage;
- b. type of vessel and propulsion system;
- c. nature of cargo carried; and
- d. waste categories presenting higher pollution risk.

4. Recording of Satisfaction

Any exemption granted under rule 26(2) shall be recorded in writing and shall include:

- a. waste categories covered;
- b. quantities exempted;
- c. validity limited to the specified voyage or port call; and
- d. reasons for grant.

Non-derogation

Nothing in this Schedule shall be construed as permitting any discharge of vessel-generated waste into the sea in contravention of the MARPOL Convention.

FORM- CPIR-1
(See Rule 36)
COASTAL POLLUTION INCIDENT REPORT

1. Vessel / Facility Details

- Vessel Name: _____
- IMO Number: _____
- Flag: _____
- Agent: _____

2. Type of Pollution Threat

- Oil / Oily mixture / Sludge
- Noxious liquid substance
- Chemical / HNS
- Sewage
- Garbage (specify category)
- Other harmful substance: _____

3. Estimated Quantity Released / Threatened

4. Location (Coordinates/Berth)

5. Time of Incident

6. Cause (if known)

7. Actions Taken

- Containment booms deployed
- Scuppers plugged
- Pumping stopped
- Emergency pollution control activated
- Notification to terminal or port

8. Impact Assessment (coastal waters / fisheries / marine life):

9. Attachments

- Photos/videos
- Log extracts
- Sounding records
- Tank data

10. Certification by Master

I certify that the information provided is true.

Name: _____ Signature: _____
Date: _____

FORM I*(See Rule 40)***FORM FOR NOTIFICATION OF NAVIGABLE RIVERS OR CHANNELS LEADING TO A PORT****1. Title of the Notification**

(Short descriptive title indicating the designated stretch of river/ channel)

2. Description of the River/Channel Declared as Navigable Access Route**(a) Name of River/Channels leading to a port:****(b) Geographical coordinates and any other components, as may be applicable:**

- Latitude: _____ Longitude: _____

3. Navigational Aids and Markings (as applicable):

4. Purpose of Notification:

5. Instructions (if any):

6. Date of Commencement:

The notification shall come into force on _____

7. Authority Issuing the Notification:

Name of Department/Ministry: _____

Signature: _____

Name: _____

Designation: _____

Seal: _____

Date: _____

Place: _____

Notes (for the Gazette printer / Port Authority use)

1. The filled form must be published verbatim in the Official Gazette.
2. A digital version of this form shall be uploaded on Government and concerned port website

FORM II
(See Rule 45)
FORM FOR NOTIFICATION OF A NEW PORT

1. Title of Notification

2. Name of the New Port

3. Geospatial Description of Port Limits

(a) Landward Boundary (if applicable)

Description and coordinates:

(b) Seaward Boundary

Coordinates:

- Point 1: Lat ____ Long ____
- Point 2: Lat ____ Long ____
- Point 3: Lat ____ Long ____

(Additional points may be added as required)

(c) Channels leading to port and Navigational Access:

4. Hydrographic and Navigational Features:

(Attach charts/maps if required)

5. Purpose and Applicability:

(Describe port functions: cargo handling, passenger operations, offshore terminals, etc.)

6. Effective Date of Notification:

7. Issuing Authority:

Name: _____

Designation: _____

Department: _____

Signature: _____

Seal: _____

Date: _____

Place: _____

FORM III
(See Rule 45)
FORM FOR ALTERATION OF EXISTING PORT LIMITS

1. Title of Notification:

2. Name of the Port:

3. Nature of Alteration:

- Extension of limits
- Reduction of limits
- Modification of coordinates
- Inclusion of new channels leading to port/anchorage
- Exclusion of area
- Other (specify): _____

4. Revised Coordinates of Port Limits:

5. Justification for Alteration:

(Expansion: dredging, new terminals; Restriction: safety, environmental zones, etc.)

6. Maps/Charts Attached:

7. Effective Date:

8. Issuing Authority:

Name: _____

Designation: _____

Signature: _____

Seal: _____

Date: _____

Place: _____

[F. No. PD-24015/1/2025-PD1/E-378148]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.